चैत्र शुक्ल - 6 ■ संवत 2081 ■ वर्ष - 12 ■ अंक - 245 ■ पृष्ठ - 8 ■ रु. 5/- चेन्नई » शुक्रवार » 04-04-2025 ■ www.dakshinbharat.com ■ Email : chennai@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷின் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினசரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित

4 द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 25 के माध्यम से में आईफा जैसे आयोजनों के लिए बनेंगी संभावनाएं

6 संघ की राय के बाद अध्यक्ष का नाम तय!

7 म्यूनिख की सड़क पर अनुपम खेर ने गाया गाना

फर्स्ट टेक

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपनी संपत्ति की घोषणा करेंगे

नई दिल्ली/भाषा। न्यायपालिका में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने पदभार ग्रहण करते ही सार्वजनिक तौर पर अपनी संपत्ति की घोषणा करने पर सहमति जताई है। पूर्ण पीठ की एक बैठक में शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति का खुलासा करने का निर्णय लिया और इसका विवरण उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर कहा गया है कि संपत्ति की घोषणा करना स्वैच्छिक आधार पर होगा। भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना सहित उच्चतम न्यायालय के 30 न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति की घोषणा प्रस्तुत की है।

नेतन्याहू अंतरराष्ट्रीय वारेंट के बावजूद बुडापेस्ट पहुंचे, हंगरी बोला- आईसीसी से अलग होंगे

बुडापेस्ट/एपी। इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बृहस्पतिवार तड़के हंगरी की राजधानी पहुंचे जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। हालांकि विश्व की शीर्ष युद्ध अपराध अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है। नवंबर में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) ने नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी किया था जिसके बाद से यह इजराइली प्रधानमंत्री की दूसरी विदेश यात्रा है। जैसे ही नेतन्याहू बुडापेस्ट पहुंचे, हंगरी ने कहा कि वह आईसीसी से अलग होने की प्रक्रिया शुरू करेगा।

तेलंगाना में पेड़ों की कटाई के मामले में किसी भी गतिविधि पर रोक

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को तेलंगाना सरकार से हैदराबाद विश्वविद्यालय के बगल में स्थित भूखंड पर लगे बड़े वृक्षों को हटाने की ''मजबूरी'' के बारे में स्पष्टीकरण मांगा तथा अगले आदेश तक किसी भी प्रकार की गतिविधि पर रोक लगा दी। राज्य में पेड़ों की कटाई को ''बहुत गंभीर मामला'' बताते हुए न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि तेलंगाना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा उसके समक्ष पेश की गई अंतरिम रिपोर्ट ''चिंताजनक तस्वीर'' पेश करती है। रिपोर्ट में अदालत को बताया गया कि बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं। पीठ ने कहा, ''हम निर्देश देते हैं कि अगले आदेश तक, पहले से मौजूद पेड़ों के संरक्षण के अलावा, किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि राज्य द्वारा नहीं की जाएगी।''

वक्फ विधेयक से जमीन हड़पने पर लगेगी रोक : रिजिजू

राज्यसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक 2025 पेश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/एजेन्सी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को राज्यसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक 2025 पेश करते हुए कहा कि ये विधेयक किसी की धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि वक्फ बोर्डों की जवाबदेही , पारदर्शिता तथा दक्षता बढाने के लिए लाये गये हैं । उन्होंने कहा कि यह विधेयक देश में एक नया सवेरा लेकर आया है और इसीलिए इस एक्ट का नाम 'उम्मीद' रखा गया है। इसमें कलेक्टर से लेकर बोर्ड के हर व्यक्ति की भूमिका को पारदर्शिता के साथ जवाबदेह बनाया गया है। इसका उद्देश्य सबका सशक्तिकरण करना है। इससे जहां जमीन हड़पने की मनमानी प्रक्रिया पर रोक लगेगी वहीं करोड़ों गरीब मुसलमानों का जीवन आबाद होगा।

रिजिजू ने कहा कि अब वक्फ बोर्डों का केन्द्रीकृत डेटाबेस रहेगा और सभी वक्फ संपत्ति का पूरी तरह से पंजीकरण कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे ज्यादा संपत्ति भारत में वक्फ बोर्ड के पास है लेकिन गरीबों को इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि आज से पहले कोई भी विधेयक इतने विचार विमर्श के बाद नहीं लाया गया है। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इस विधेयक को तैयार करने से पहले देशभर में सभी हितधारकों से साथ व्यापक विचार विमर्श किया था। इसके बाद संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष 284 संगठनों और सभी हितधारकों ने ज्ञापन दिये और 97 लाख लोगों ने अपने मत रखे। संयुक्त समिति ने दस शहरों में जाकर लोगों से बात की है। इस तरह से इस विधेयक पर एक करोड़ से ज्यादा सुझाव मिले हैं। उन्होंने विधेयक को असंवैधानिक बताने और मुसलमानों का हक छीनने के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम का हस्तक्षेप नहीं होगा। वक्फ बोर्ड का प्रबंधन करने वाला 'मुतवल्ली' मुस्लिम ही रहेगा।

रिजिजू ने कहा कि यह विधेयक इसलिए भी लाना जरूरी हो गया था कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने 5 मार्च 2014 को लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले राजधानी दिल्ली की 123 प्रमुख संपत्तियों को इनसे संबंधित मामले न्यायालय में लंबित होने के बावजूद गैर अधिसूचित कर वक्फ बोर्ड को सौंप दिया था। उन्होंने कहा कि मौजूदा विधेयक में इस संबंध में समय समय पर गठित तीन समितियों की सिफारिशों को शामिल किया गया है। इसमें कांग्रेस के समय में गठित की गयी समिति भी शामिल हैं।

अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकार छीन रही है सरकार : खरगे

नई दिल्ली/एजेन्सी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकार छीन रही है। उन्होंने सदन में विधायक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि देश में ऐसा माहौल बन रहा है कि यह विधेयक अल्पसंख्यक समुदाय को परेशान करने के लिए है। विधेयक में कई ऐसे तथ्य और संदर्भ दिए गए हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं है। खरगे ने कहा कि लोकसभा में विधेयक को विभाजन से पारित किया गया और मत विभाजन में बड़ा अंतर नहीं था। इसका तात्पर्य है कि विधेयक में कमियां है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से सरकार और अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आवंटन में लगातार कटौती कर रही है।

विकास की नीति में विश्वास करते हैं भारत और थाईलैंड : मोदी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति और हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण में थाईलैंड का विशेष स्थान है।

बैंकाक/भाषा। भारत और थाईलैंड ने अपने संबंधों को प्रगाढ़ कर रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का बृहस्पतिवार को फैसला किया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मुक्त, समावेशी और नियम आधारित व्यवस्था का समर्थन करते हैं तथा विस्तारवाद के बजाय विकास की नीति में विश्वास करते हैं।

मोदी ने यह टिप्पणी थाईलैंड की अपनी समकक्ष पैतोंगतार्न शिनावात्रा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त प्रेस सम्मेलन में की। इस वार्ता के दौरान उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर व्यापक चर्चा की।

मोदी ने शिनावात्रा के साथ हुई बातचीत के बारे में कहा, हमने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और थाईलैंड के बीच पर्यटन, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया है। हमने आपसी व्यापार, निवेश और व्यवसायों के बीच आदान-प्रदान बढ़ाने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि एमएसएमई, हथकरघा और हस्तशिल्प में सहयोग के लिए भी समझौते किए गए हैं। मोदी ने कहा कि भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति और हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण में थाईलैंड का विशेष स्थान है। मोदी ने कहा, आज हमने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। सुरक्षा एजेंसियों के बीच 'रणनीतिक वार्ता' स्थापित करने पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भारत आसियान में एकता और केंद्रीयता का पूर्ण समर्थन करता है।

मोदी ने कहा, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हम दोनों एक मुक्त, समावेशी और नियम-आधारित व्यवस्था का समर्थन करते हैं। हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा, मैं अपनी यात्रा के अवसर पर 18वीं शताब्दी के 'रामायण' भित्ति चित्रों पर आधारित एक विशेष डाक टिकट जारी करने के लिए थाईलैंड सरकार का आभारी हूं।

ममता सरकार को झटका

25,000 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने के फैसले पर उच्चतम न्यायालय की मुहर

भर्ती की पूरी प्रक्रिया को 'दूषित' और 'सुधार से परे दागदार' घोषित किया

नई दिल्ली/एजेन्सी। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में 25,000 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले पर गुरुवार को मुहर लगा दी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। पीठ ने अपने फैसले में पश्चिम बंगाल के स्कूलों में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के पदों पर भर्ती की पूरी प्रक्रिया को 'दूषित' और 'सुधार से परे दागदार' घोषित किया। अदालत ने कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया हेरफेर और धोखाधड़ी से दूषित थी और इसे सुधारा नहीं जा सकता। न्यायालय ने कहा कि इस प्रक्रिया की पवित्रता और विश्वसनीयता को नष्ट कर दिया गया है। ऐसे में दागी उम्मीदवारों की सेवाएं समाप्त करने के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई वैध आधार नहीं है। पीठ ने कहा, चूंकि नियुक्तियां धोखाधड़ी और जालसाजी से हुई हैं, इसलिए हमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं दिखता। शीर्ष न्यायालय ने हालांकि कुछ निर्देशों में संशोधन किया। शीर्ष न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा कि जो उम्मीदवार पहले कहीं और कार्यरत थे, उन्हें अपने पिछले पदों पर वापस आने की अनुमति दी जाएगी। न्यायालय ने राज्य सरकार से तीन महीने की अवधि के भीतर चयन की नई प्रक्रिया शुरू करने को कहा। उच्च न्यायालय के निर्देश पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की गई जांच में पश्चिम बंगाल के तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और अन्य को गिरफ्तार किया गया था तथा भारी मात्रा में नकदी भी बरामद की गई थी।

देश में यूरोपीय मानक की बसें चलेंगी, 'हथौड़ेछाप' बसें नहीं : गडकरी

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बस हादसों में लोगों की होने वाली मौत पर चिंता जताते हुए बृहस्पतिवार को लोकसभा में कहा कि अब यूरोपीय मानक वाली बसें परिचालित किये जाने और 'हथौड़ेछाप' बसें संचालित नहीं होने देने को सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए, देश के कई हिस्सों में विनिर्मित होने वाली उन बसों का उल्लेख किया जो सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता नहीं हैं। गडकरी ने कहा, ''अब देश में यूरोपीय मानक वाली बसें चलेंगी, हथौड़ेछाप बसें नहीं चलेंगी।'' उन्होंने ट्रक चालकों की सुरक्षा को लेकर कहा, ''अब हमारे विभाग ने तय किया है कि कोई भी ट्रक एयरकंडीशन के केबिन के बिना (परिचालन के लिए) नहीं आएगा। अगर यहां (लोकसभा में) एसी नहीं होता, तो हमारी हालत क्या होती। इसलिए, हमने इसे (ट्रकों में एसी वाले केबिन) को अनिवार्य बनाया है।

वैश्विक व्यवस्था में हो रही उथल-पुथल, हर क्षेत्र को अपने बारे में स्वयं सोचना होगा : जयशंकर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बैंकाक/भाषा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित जवाबी शुल्क के बीच, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बृहस्पतिवार को कहा कि दुनिया 'स्व-सहायता' के युग की ओर बढ़ रही है और हर क्षेत्र को खुद पर ध्यान देना होगा।

जयशंकर ने बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक) के 20वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि छोटी आपूर्ति शृंखलाएं और निकट पड़ोसी अब पहले की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। उन्होंने कहा, ''वास्तविकता यह है कि दुनिया स्व-सहायता के युग की ओर बढ़ रही है। हर क्षेत्र को खुद पर ध्यान देने की जरूरत है, चाहे वह खाद्य, ईंधन और उर्वरक आपूर्ति, टीके या त्वरित आपदा प्रतिक्रिया हो।''

विदेशमंत्री ने कहा, ''हम अपनी आंखों के सामने इसे घटित होते देख रहे हैं। समय वास्तव में बदल गया है। छोटी आपूर्ति शृंखलाएं और निकट पड़ोसी पहले की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं।''

जयशंकर जहां बिम्सटेक मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए यहां हैं। वहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बृहस्पतिवार को यहां पहुंचे।

मंत्री ने कहा कि बिम्सटेक शिखर सम्मेलन ''बहुत अनिश्चित और अस्थिर समय में हो रहा है जबकि वैश्विक व्यवस्था उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है।'' उन्होंने कहा, ''इससे हमें बिम्सटेक को और अधिक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए। नई व्यवस्था, जिसकी रूपरेखा अब दिखाई देने लगी है, मूल रूप से अधिक क्षेत्रीय और एजेंडा-विशिष्ट है।''

मंत्री ने कहा, ''वह युग जब कुछ शक्तियां अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को अपने हाथ में लेती थीं, अब पीछे छूट चुका है। हम अपनी संभावनाओं को किस तरह से देखते हैं, यह काफी हद तक हम पर निर्भर करता है। कई चुनौतियां का सामना कर रहे विकासशील देशों के लिए अकेले इनसे निपटने के बजाय एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करना बेहतर है।''

जयशंकर ने रेखांकित किया कि भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष रूप से सड़कों, रेलवे, जलमार्गों, ग्रिडों और पाइपलाइन के नेटवर्क के साथ बिम्सटेक के लिए संपर्क केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा, ''त्रिपक्षीय राजमार्ग का पूरा होना भारत के उत्तर पूर्व को प्रशांत महासागर तक जोड़ देगा, जो वास्तव में एक परिवर्तनकारी कदम होगा।''

जयशंकर ने यह भी कहा कि बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों के साझा हित और साझा चिंताएं हैं, जो इतिहास से उपजी हैं । उन्होंने कहा, ''चाहे वह बिम्सटेक सदस्यों के बीच संपर्क, व्यापार, निवेश या सेवाएं हों, हम अपनी वास्तविक क्षमता से कम प्रदर्शन कर रहे हैं।''

ट्रंप ने भारत पर 27 प्रतिशत शुल्क लगाया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

वाशिंगटन/नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को माल निर्यात करने वाले सभी देशों पर सार्वभौमिक शुल्क लगा दिया है तथा भारत जैसे देशों पर अतिरिक्त भारी शुल्क लगा दिया है, जिससे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में झींगा से लेकर इस्पात तक के उत्पादों की बिक्री पर असर पड़ सकता है।

अमेरिका ने भारत से आयातित सभी वस्तुओं पर 27 प्रतिशत का भारी शुल्क लगा दिया है, जिसमें फार्मास्युटिकल्स, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा और कुछ खनिज पदार्थ शामिल नहीं हैं। ये उत्पाद अमेरिका में उपलब्ध नहीं हैं। अमेरिका ने भारत को अनुचित व्यापार प्रथाओं का 'सबसे खराब अपराधी' बताते हुए उस पर शुल्क लगाया है। अमेरिका को झींगा, कालीन, चिकित्सा उपकरण और सोने के आभूषण जैसे उत्पादों का निर्यात प्रभावित होगा। दूसरी ओर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा और फार्मा के निर्यात को उसके प्रतिस्पर्धी देशों पर बढ़त मिलेगी।

ऊर्जा को शुल्क से छूट देने का मतलब यह भी होगा कि भारत अमेरिका को गैसोलिन और गैसोलीन जैसे ईंधन का निर्यात जारी रख सकता है। शुल्क से छूट प्राप्त सामान भारत से अमेरिका को होने वाले कुल निर्यात का लगभग 25 प्रतिशत है।

ट्रंप ने सभी व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 10 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त मूल्यानुसार शुल्क लगाने की घोषणा की। भारत पर 10 प्रतिशत का आधारभूत शुल्क पांच अप्रैल से और अतिरिक्त 27 प्रतिशत शुल्क नौ अप्रैल से प्रभावी होगा।

अमेरिकी शुल्क पर 'इंतजार करो और देखो' की नीति अपनाएगा भारत

नई दिल्ली/भाषा। भारत वैश्विक व्यापार पर अमेरिका द्वारा अतिरिक्त आयात शुल्क लगाए जाने से उत्पन्न स्थिति पर नजर रखेगा तथा जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगा। इसकी वजह यह है कि अमेरिका को खुद अपने घरेलू उद्योग से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सरकारी सूत्रों ने यह बात कही है। अधिकारी ने कहा कि भारत के लिए चुनौतियां और अवसर, दोनों हैं, क्योंकि निर्यात में उसके कई प्रतिस्पर्धी देश जैसे चीन, वियतनाम, बांग्लादेश, कंबोडिया और थाइलैंड उच्च शुल्क का सामना कर रहे हैं। सूत्र ने कहा, एक देश के तौर पर हमें स्थिति पर नजर रखने की ज़रूरत है और जल्दबाज़ी करने की जरूरत नहीं है। यह कुछ नया हुआ है। यह अभूतपूर्व है। अमेरिकी उद्योग भी इस कदम से नाराज होंगे और चुनौतियां भी होंगी। हमें इंतजार करने, निरीक्षण करने और देखने की जरूरत है क्योंकि हमें यह निष्कर्ष निकालने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि यह भविष्य के लिए है। हमें यह देखने की जरूरत है कि उनके पक्ष में क्या है। अमेरिका द्वारा आयात शुल्क बढ़ाने का उद्देश्य व्यापार घाटे में कमी लाना तथा विनिर्माण को बढ़ावा देना है। भारत पर 27 प्रतिशत शुल्क के बारे में उन्होंने कहा कि केवल छह-सात क्षेत्र जैसे झींगा और कालीन को भारी करों से चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अधिकांश अन्य क्षेत्रों को निर्यात बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

केकेआर ने सनराइजर्स को हराया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। वेंकटेश अय्यर ने अपने आलोचकों को जवाब देते हुए 29 गेंद में 60 रन बनाये जिसकी मदद से कोलकाता नाइट राइडर्स ने बृहस्पतिवार को आईपीएल के मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 80 रन से शिकस्त दी । अंगकृष रघुवंशी (32 गेंद में 50 रन) ने भी पचासा जड़ा और कप्तान अजिंक्य रहाणे (27 गेंद में 38 रन) के साथ 81 रन की साझेदारी की जिसके दम पर मेजबान टीम ने छह विकेट पर 200 रन बनाये ।

जवाब में सनराइजर्स की टीम 16 . 4 ओवर में 120 रन पर आउट हो गई । तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा ने ट्रेविस हेड (चार) और ईशान किशन (दो) को लगातार दो ओवरों में आउट किया । उन्होंने चार ओवर में 29 रन देकर तीन विकेट चटकाये ।

हर्षित राणा ने अभिषेक शर्मा (दो) का विकेट लिया तब सनराइजर्स का स्कोर तीसरे ओवर में नौ रन पर तीन विकेट था । आंद्रे रसेल और सुनील नारायण ने भी एक एक विकेट लिये । सनराइजर्स ने दस ओवर तक पांच विकेट 66 रन पर गंवा दिये थे । इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने दो गेंद के भीतर दो विकेट लेकर निचले क्रम को रवाना किया । उन्होंने चार ओवर में 22 रन देकर तीन विकेट लिये ।

गत चैम्पियन केकेआर पहले तीन में से दो मैच गंवाने के बाद जीत की राह पर लौटी है । अब उसे मंगलवार को लखनऊ सुपर जाइंट्स से खेलना है ।

04-04-2025 सूर्यास्त 6:20 बजे | 05-04-2025 सूर्योदय 6:02 बजे

BSE 76,295.36 (-322.08) | NSE 23,250.10 (-82.25)

सोना 9,244 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम | चांदी 110,000 रु. प्रति किलो

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

बाबा रे बाबा

पढ़ लिख कर वो बेकार फिरा,
बस चना-चबेना ही चाबा।
ना भागा कभी लोन लेकर,
ना माल किसीका भी दाबा।
बेचूं क्या चाय पकौड़े तल,
या खोलूं इक सस्ता ढाबा।
उलझन सुलझी जब बन बैठा,
बाबू की जगहां वो बाबा।।

कठुआ में आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान 12वें दिन भी जारी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जम्मू/भाषा। जम्मू-कश्मीर के कठुआ में तीन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए कई एजेंसियों द्वारा शुरू किया गया तलाशी अभियान बृहस्पतिवार को लगातार 12वें दिन भी जारी रहा। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान से घुसपैठ कर भारतीय सीमा में दाखिल हुए आतंकवादी कठुआ के घने जंगलों में छिपे हुए हैं।

सुरक्षा एजेंसियां भी आतंकवादियों के समर्थकों पर नकेल कस रही हैं और घात लगाकर हमले कर रही हैं। बहु-स्तरीय घेराबंदी को मजबूत करने तथा क्षेत्र में छह-सात किलोमीटर के दायरे में घात लगाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। एक अधिकारी ने कहा, ''सुरक्षा एजेंसियों का तलाशी अभियान जारी है। यह भाग रहे आतंकवादियों को पकड़ने के लिए जारी है। ''

तलाशी अभियान को हवाई निगरानी के साथ तेज कर दिया गया, जिसमें हेलीकॉप्टरों, यूएवी और खोजी कुत्तों का उपयोग भी शामिल था। अधिकारियों ने बताया कि सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी), पुलिस, विशेष अभियान समूह (एसओजी), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के संयुक्त दल पूरे क्षेत्र की तलाशी ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि दुर्गम इलाकों और घने जंगली इलाकों में अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आतंकवादी ऊपरी इलाकों की ओर भाग न सकें। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों को समर्थन देने वाले भूमिगत नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां ओजीडब्ल्यू पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं और पहाड़ियों में भोजन, आश्रय और मार्गदर्शन की आपूर्ति को रोकने के लिए उन पर कार्रवाई कर रही हैं।

ट्रंप की शुल्क घोषणा से सेंसेक्स 322 अंक टूटा, आईटी शेयरों में बिकवाली

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। स्थानीय शेयर बाजार में बृहस्पतिवार को गिरावट आई और बीएसई सेंसेक्स 322 अंक टूट गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत समेत 60 देशों पर जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा के बाद सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) शेयरों में बिकवाली तथा वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख से बाजार नुकसान में रहा।

तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 322.08 अंक यानी 0.42 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76,295.36 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 809.89 अंक तक लुढ़क गया था। हालांकि, बाद में औषधि शेयरों में तेजी से बाजार नुकसान की कुछ हद तक भरपाई करने में सफल रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 82.25 अंक यानी 0.35 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,250.10 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी एक समय 186.55 अंक तक लुढ़क गया था। अमेरिका ने भारत पर 27 प्रतिशत का जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि अमेरिकी वस्तुओं पर भारत उच्च आयात शुल्क वसूलता है, ऐसे में अब देश के व्यापार घाटे को कम करने और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाना जरूरी था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक स्तर पर अमेरिकी उत्पादों पर लगाए गए उच्च शुल्क दरों का मुकाबला करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए लगभग 60 देशों पर जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की है।

रेलिगेयर ब्रोकिंग लि. के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) अजित मिश्रा ने कहा, ''अमेरिकी शुल्क की घोषणा के बाद निफ्टी सूचकांक नुकसान के साथ खुला लेकिन कुछ प्रमुख कंपनियों के शेयरों में मजबूती से इसमें कुछ सुधार देखने को मिला। इससे शुरुआती नुकसान को कम करने में मदद मिली और आज बाजार एक दायरे में रहा।'' सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारती एयरटेल और मारुति सुजुकी इंडिया, टाटा स्टील के शेयरों में प्रमुख रूप से गिरावट आई।

श्रेयांश पारणा समिति द्वारा वर्षीतप पारणा महोत्सव की तैयारियां जोरों पर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर की श्रेयांस पारणा समिति द्वारा आचार्य पार्श्वचंद्रजी एवं डॉ. पदमचंद्रमुनिजी के सान्निध्य में अक्षय तृतीया के अवसर पर 30 अप्रैल को वर्षीतप आराधकों के पारणा महोत्सव का आयोजन पैलेस ग्राउंड स्थित त्रिपुरावासिनी सभागार में होगा। समिति के चेयरमैन रमेशचंद सियाल एवं सहचेयरमैन मीठालाल लोढ़ा ने बताया कि इस अक्षय तृतीया पारणा महोत्सव में 160 स्थानीय वर्षीतप आराधकों सहित विभिन्न नगरों से कुल मिलाकर लगभग 250 तपस्वियों का पारणा संपन्न होगा। समिति द्वारा श्रीरामपुरम् स्थित जेपीपी जैन श्रमणी सेंटर में संचालित वर्षीतप आराधकों के एकांतर पारणा के पश्चात 1 दिवसीय पारणा के लाभार्थी गौतमचंद अनिलकुमार गन्ना परिवार, रोशनलाल, चन्द्रेशकुमार, तेजमल कांठेड़ परिवार, अजीतकुमार दौलतकुमार सिद्धार्थ चपलोत परिवार का सम्मान किया गया।

राजेन्द्रकुमार नाहर, महेन्द्रकुमार मेहता, महावीरचंद श्रीश्रीमाल, जेके महावीरचंद चौरड़िया, महेंद्रकुमार चौरड़िया, रमेशकुमार गुगलिया, रोशनलाल नाहर, कोमलचंद धोका ने तपस्वियों के एकांतर पारणा की सेवा एवं अनुमोदना का लाभ लिया।

बीएसएनएल लाभप्रद निकाय बनने और ग्राहक संतुष्टि के पथ पर अग्रसरः सिंधिया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा को सूचित किया कि सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल लाभप्रद निकाय बनने और ग्राहकों को संतुष्टि देने के रास्ते पर है। उन्होंने कहा कि कंपनी को 18 साल बाद पहली बार अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 262 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है और पिछले छह महीनों में 55 लाख उपयोगकर्ता जुड़े हैं ।

उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते सिंधिया ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी को लाभप्रद स्थिति में लाने और इसके ग्राहक आधार में सुधार करने के प्रयास जारी हैं। सिंधिया ने राज्यसभा को बताया, ''18 साल बाद, बीएसएनएल ने पहली बार अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 262 करोड़ रु. का शुद्ध लाभ हासिल किया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 18 साल में पहली बार ऐसा हुआ है।'' बीएसएनएल को 2023-24 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 1,262 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जबकि इस साल इसी तिमाही में 262 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। इस दौरान कंपनी ने 1,500 करोड़ रुपए का परिचालन लाभ दर्ज किया। बीएसएनएल ने पिछले साल जून से अब तक 55 लाख ग्राहक जोड़े हैं। उन्होंने कहा, ''आपको यह जानकर खुशी होगी कि जून 2024 से फरवरी 2025 तक बीएसएनएल इतिहास में पहली बार 8.55 करोड़ ग्राहकों से बढ़कर 9.1 करोड़ ग्राहक वाला हो गया है। हमने पिछले छह से सात महीनों में 55 लाख ग्राहक जोड़े हैं।''

लोकसभा में बृहस्पतिवार को पांच घंटे चला शून्यकाल, 202 सांसदों ने रखी अपनी बात

नई दिल्ली/भाषा। लोकसभा में बृहस्पतिवार को पांच घंटे से अधिक समय तक शून्यकाल चला, जिस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद अनुराग ठाकुर समेत 202 सांसदों ने अलग-अलग विषयों पर अपनी बात रखी।

लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल से लोकसभा में शून्यकाल का समय बढ़ाया गया ताकि जन प्रतिनिधियों को संसद में अपने क्षेत्र की बात रखने का पूरा अवसर मिल सके।

उन्होंने बताया, ''आज 5 घंटे से अधिक समय तक शून्य काल चला, इस दौरान 202 सांसदों ने अपनी बात रखी। इससे पहले 18 जुलाई 2019 को विस्तारित शून्य काल में 161 सांसदों ने अपनी बात रखी थी।''

कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की पिछली बैठक में बिरला ने शून्यकाल का समय बढ़ाने का आश्वासन दिया था।

ओला इलेक्ट्रिक ने वाहनों की उसी दिन पंजीकरण और डिलिवरी की सुविधा शुरू की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। ओला इलेक्ट्रिक ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने वाहनों के उसी दिन पंजीकरण और डिलिवरी की पहल शुरू की है।

बेंगलूरु स्थित फर्म ने बयान में कहा, ''हाइपरडिलिवरी का प्रायोगिक दौर, बेंगलूरु में शुरू हुआ है और इस तिमाही के दौरान चरणबद्ध तरीके से पूरे भारत में इसका विस्तार किया जाएगा।''

ग्राहक अब अपनी खरीदारी ऑनलाइन या ओला इलेक्ट्रिक स्टोर पर पूरी कर सकते हैं और अपने पूरी तरह से पंजीकृत वाहनों पर कुछ ही घंटों में घर जा सकते हैं।

ओला इलेक्ट्रिक के प्रवक्ता ने कहा, ''हमने एआई-आधारित स्वचालन के माध्यम से और पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी तरह से आंतरिक करके वाहनों के पंजीकरण के प्रसंस्करण समय में काफी कमी की है।''

उन्होंने कहा, ''इसके साथ हम अपने ग्राहकों के लिए बहुत ही सहज खरीदारी अनुभव सुनिश्चित कर रहे हैं, थकाऊ खरीद प्रक्रियाओं और लंबी डिलिवरी समयसीमा को खत्म कर रहे हैं।

'विकसित भारत' दृष्टिकोण के लिए नवोन्मेषण का वित्तपोषण जरूरी : एसोचैम

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष संजय नायर ने कहा है कि देश का 'विकसित भारत' का दृष्टिकोण मूल रूप से वैश्विक प्रतिस्पर्धा और नवाचार पर निर्भर करता है, जिसके लिए कृषि, स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए स्टार्टअप को काफी अधिक वित्तपोषण की आवश्यकता होती है।

एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) के अध्यक्ष नायर ने विशेष रूप से कृत्रिम मेधा (एआई) और रक्षा में 'डीपटेक' टिकाऊ समाधान बनाने की दिशा में रणनीतिक रूप से पूंजी लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने यहां स्टार्टअप महाकुंभ-2025 के दौरान कहा, विकसित भारत के लिए हमारा दृष्टिकोण मूल रूप से इस तथ्य पर निर्भर करता है कि हम वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और नवाचार-संचालित होने जा रहे हैं। ...और जब हमने पिछले दशक में 150 अरब डॉलर से अधिक जुटाए हैं, तो मुझे लगता है कि हमें बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता है।

नायर ने उद्यम पूंजी से परे वित्तपोषण तंत्र में विविधता लाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जिसमें ऋण वित्तपोषण, सार्वजनिक वित्तपोषण और राज्य वित्तपोषण विकल्प शामिल किए जाएं।

तीन से पांच अप्रैल तक आयोजित हो रहे स्टार्टअप महाकुंभ में 50 से अधिक देशों के स्टार्टअप, निवेशक और उद्योग जगत के दिग्गज एक साथ आएंगे।

कनिष्ठ छात्र की रैगिंग करने के आरोप में तीन मेडिकल छात्र निलंबित

हैदराबाद/भाषा। तेलंगाना में नागरकुरनूल जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज के तीन छात्रों को प्रथम वर्ष के एमबीबीएस छात्र की रैगिंग करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बुधवार को रैगिंग रोधी समिति की बैठक के बाद तीन वरिष्ठ छात्रों (एक तृतीय वर्ष का और दो द्वितीय वर्ष) के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई।

कॉलेज के अधिकारियों ने बताया कि रैगिंग रोधी समिति ने तीनों छात्रों पर जुर्माना लगाया है, उन्हें कॉलेज में शैक्षणिक गतिविधियों से प्रतिबंधित कर दिया है तथा एक से तीन महीने के लिए छात्रावास से निष्कासित कर दिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने तीनों छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कनिष्ठ छात्र ने उन पर 25 मार्च को संस्थान के छात्रावास के कमरे में रैगिंग करने का आरोप लगाया था।

क्या प्रमुख मंदिरों का प्रबंधन करने वाले न्यासों में गैर हिंदुओं को जगह मिलेगी : जलील

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

छत्रपति संभाजीनगर/भाषा। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन (एआईएमआईएम) के नेता और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि सरकार मौजूदा वक्फ अधिनियम में संशोधन करके बड़े उद्योगपतियों को जमीन सौंपना चाहती है। उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रमुख मंदिरों का प्रबंधन करने वाले न्यासों में गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति की जाएगी।

जलील ने संवाददाताओं के साथ बातचीत में दावा किया कि लोकसभा द्वारा पारित और बृहस्पतिवार को राज्यसभा में पेश किया गया वक्फ (संशोधन) विधेयक, उन नेताओं को बचाने का प्रयास करता है जिन्होंने वक्फ संपत्तियों पर कब्जा किया है। एआईएमआईएम की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष ने विधेयक में प्रस्तावित वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति के पीछे के औचित्य पर सवाल उठाया और जानना चाहा कि क्या अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि बड़े मंदिरों का प्रबंधन करने वाले न्यासों में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने सवाल किया, ''अगर वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति की जा रही है, तो क्या वे इम्तियाज जलील को शिरडी साईंबाबा (मंदिर) ट्रस्ट या तिरुपति मंदिर ट्रस्ट में शामिल करेंगे।

केंद्र ने गाचीबोवली जंगल में पेड़ों की कटाई पर तेलंगाना से रिपोर्ट मांगी है : भूपेंद्र यादव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बृहस्पतिवार को बताया कि केंद्र ने तेलंगाना सरकार को नोटिस भेजकर हैदराबाद विश्वविद्यालय (यूओएच) परिसर के पास कांचा गाचीबोवली वन क्षेत्र में 400 एकड़ भूमि पर पेड़ों की कथित कटाई पर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है।

राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए यादव ने कहा, ''हैदराबाद में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि राज्य सरकार को उन पेड़ों और हरित क्षेत्र से आखिर कैसी दुश्मनी है कि उन्हें रात के अंधेरे में अभियान चलाना पड़ रहा है।'' यादव ने कहा, ''राज्य सरकार ने 400 से अधिक पेड़ काटे हैं। मोर जैसे पक्षी की प्रजातियों को भगाया जा रहा है और आप इसे वीडियो और तस्वीरों में देख सकते हैं।'' उन्होंने कहा, ''इस संबंध में हमने मुख्य सचिव को नोटिस भेजा है और तथ्यात्मक रिपोर्ट भी मांगी है। हम निश्चित रूप से इस मामले पर कार्रवाई करेंगे।''

यादव बीआरएस सदस्य रविचंद्र वड्डीराजू के पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे जिन्होंने कथित तौर पर नष्ट किए जा रहे हरित आवरण को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी थी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) की सदस्य डॉ फौजिया खान द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में बड़ी संख्या में रिक्तियों को लेकर उठाई गई चिंताओं पर कहा कि तकनीकी और वैज्ञानिक दोनों तरह के 11,562 पद रिक्त हैं और महीने के अंत तक सभी पद भर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, ''हमने इन पदों के लिए मंजूरी दे दी है और हमने यह भी तय किया है कि 30 अप्रैल तक सभी पद भर दिए जाएंगे।''

'एयर शेड' मुद्दे पर पूछे गए पूरक प्रश्न के उत्तर में यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार ने सबसे पहले इसे मान्यता दी। उन्होंने कहा ''दिल्ली में, हम सीक्यूएम (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) के विचार के साथ आए और इसे कानूनी दर्जा दिया।'' उन्होंने कहा, ''हमने बहुत अच्छे प्रयोग किए हैं और भविष्य में हम इस मामले पर भी कार्रवाई करने जा रहे हैं।''

वे त्रि-भाषा फॉर्मूले का सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं: डीयू कुलपति

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के कुलपति योगेश सिंह ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत प्रस्तावित त्रि-भाषा फॉर्मूले का पुरजोर बचाव किया है और आलोचना को राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया है। सिंह ने 'पीटीआई-भाषा' के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि इस नीति का विरोध अकादमिक चिंताओं पर आधारित नहीं है, बल्कि आवश्यक शैक्षिक सुधारों के प्रतिरोध पर आधारित है।

सिंह ने कहा, ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तीन भाषाओं पर जोर दिया गया है - एक मातृभाषा है और विद्यार्थी कोई भी दो अन्य भाषाएं चुन सकते हैं। मातृभाषा पर ध्यान केंद्रित किया गया है, लेकिन विकल्प खुला है।'' उन्होंने कहा, ''दक्षिण भारत में अनावश्यक भय का कोई कारण नहीं है। विद्यार्थियों को अपनी अपेक्षाओं और पसंद के अनुसार भाषा चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यह नीति विद्यार्थियों को सशक्त बनाने के लिए है, न कि उन पर कोई भाषा थोपने के लिए।'' उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था में नई चीजें हो रही हैं और यह एक बदलाव है। उन्होंने कहा कि कई बार बदलाव को स्वीकार करना मुश्किल होता है क्योंकि उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। एक आम गलत धारणा को स्पष्ट करते हुए सिंह ने शिक्षा के माध्यम और भाषा अध्ययन के बीच के अंतर को उजागर किया। उन्होंने कहा, दिल्ली विश्वविद्यालय देशभर के विद्यार्थियों को दाखिला देता है।

सरकार की नजर वक्फ की जमीन पर, अगला निशाना मंदिर ट्रस्ट की संपत्ति हो सकती है : उद्धव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। शिवसेना (उबाठा) के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि केंद्र सरकार की नजर वक्फ बोर्ड की जमीन पर है और अगला निशाना मंदिरों, गिरजाघरों और गुरुद्वारों की जमीन हो सकती है।

उद्धव ने लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पारित होने के कुछ घंटे बाद यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनकी पार्टी इस विधेयक पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कपटपूर्ण रुख और ''वक्फ की जमीन छीनकर अपने उद्योगपति मित्रों को देने की उसकी चाल'' का विरोध करती है। उन्होंने कहा, ''भाजपा और विधेयक का समर्थन करने वाले उसके सहयोगी दलों द्वारा मुस्लिम समुदाय के प्रति दिखाई गई चिंता पाकिस्तान के संस्थापक (मुहम्मद अली) जिन्ना को भी शर्मिंदा कर देगी।'' उद्धव की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने शिवसेना (उबाठा) पर वक्फ (संशोधन) विधेयक का समर्थन न करके हिंदुत्व और पार्टी संस्थापक बाल उद्धव के आदर्शों को त्यागने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ''आपकी नजर वक्फ की जमीन पर है, लेकिन मंदिर ट्रस्ट, गिरजाघरों, गुरुद्वारों के पास भी जमीन है। आपकी नजर हम (हिंदू मंदिरों की जमीन) पर भी हो सकती है। यह विधेयक सिर्फ जमीन के लिए लाया गया है। हमने इस कपट का विरोध किया है।'' उन्होंने सवाल किया, ''अगर वक्फ विधेयक मुस्लिम समुदाय की बेहतरी के लिए है, तो इसे लाकर किसने हिंदुत्व को त्यागा है। वक्फ (संशोधन) विधेयक का हिंदुत्व से क्या संबंध है? इससे हिंदुओं को क्या लाभ होगा?'' हालांकि, उद्धव ने स्वीकार किया कि विधेयक में कुछ अच्छी बातें हैं और कहा कि उनकी पार्टी नकारात्मक राजनीति का समर्थन नहीं करेगी। उन्होंने कहा, ''पारदर्शिता होनी चाहिए।''

किसान आंदोलन को फिर से खड़ा करेंगे : डल्लेवाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चंडीगढ़/भाषा। पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि किसान अपना आंदोलन फिर से खड़ा करेंगे।

डल्लेवाल ने आरोप लगाया कि राज्य की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने पुलिस कार्रवाई में शंभू और खनौरी सीमा बिंदुओं से प्रदर्शनकारियों को हटाकर उनके साथ ''विश्वासघात'' किया है। डल्लेवाल संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के वरिष्ठ नेता हैं। वह पिछले साल 26 नवंबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं, ताकि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रदान करने की कानूनी गारंटी सहित किसानों की अन्य मांगों को स्वीकार करने का केंद्र पर दबाव बनाया जा सके।

जनवरी में केंद्र द्वारा किसान नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद

डल्लेवाल ने खनौरी प्रदर्शन स्थल पर चिकित्सा सहायता लेना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने अपना अनशन समाप्त नहीं किया। बृहस्पतिवार को उन्हें पटियाला के एक निजी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। बाद में वह फरीदकोट जिले में अपने पैतृक गांव चले गए।

पटियाला में पत्रकारों से बात करते हुए डल्लेवाल ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक तरफ सरकार के साथ बैठकें हो रही हों और दूसरी तरफ बैठक के बाद किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया हो।

डल्लेवाल ने कहा, ''जिस सरकार ने हमें धोखा दिया है, वह आंदोलन को उखाड़ सकती है, लेकिन हमारा इरादा नहीं डिगा सकती। हमारा प्रयास इस आंदोलन को फिर से खड़ा करने का है। किसान संगठन एक साथ बैठेंगे और चर्चा करेंगे कि इसे पूरे देश में कैसे ले जाया जाए।''

किसान नेता ने दोहराया कि फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित किसानों की मांगें पूरी होने तक उनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रहेगी।

लोकसभा में पारित वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख करेगी द्रमुक : स्टालिन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एवं द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी पार्टी इस विधेयक के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में वाद दायर करेगी। विधेयक पारित होने के विरोध में काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकतर दलों के विरोध के बावजूद कुछ सहयोगियों के ''कहने पर'' रात दो बजे संशोधन को अपनाना संविधान के ढांचे पर हमला है। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा, यह धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला कृत्य है। इसके खिलाफ हम आज विधानसभा की कार्यवाही में काली पट्टी बांधकर भाग ले रहे हैं। लोकसभा में विधेयक पारित होने के विरोध में डीएमके विधायकों ने विधानसभा सत्र के दौरान काली पट्टियां बांधीं। मुख्यमंत्री स्टालिन ने सदन को याद दिलाया कि 27 मार्च को तमिलनाडु विधानसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेने का आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि यह धार्मिक सद्भाव को कमजोर करता है और अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

स्टालिन ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि द्रमुक की ओर से इस विवादास्पद संशोधन के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में मामला दायर किया जाएगा। तमिलनाडु, केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ लड़ेगा जो वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को नष्ट करता है और अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी को खतरे में डालता है। उन्होंने बताया कि राज्य विधानसभा ने प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ 27 मार्च को ही एक प्रस्ताव पारित कर दिया था क्योंकि यह अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के अलावा भारत के धार्मिक सद्भाव को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाला है।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने विधेयक को पारित करने के समय और तरीके की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, देश के अधिकांश राजनीतिक दलों के विरोध की अनदेखी करते हुए, रात 2 बजे इस तरह के संवेदनशील कानून को पेश करना और पारित करना, भारत के संविधान पर सीधा हमला है और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास है। उन्होंने दोहराया कि द्रमुक वक्फ (संशोधन) विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी, उन्होंने कहा कि तमिलनाडु इस कानून के खिलाफ अपनी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई जारी रखेगा। लोकसभा ने 12 घंटे की लंबी बहस के बाद गुरुवार, 3 अप्रैल को तड़के विधेयक पारित कर दिया। कुल 288 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि 232 ने इसका विरोध किया। व्यापक विरोध के बावजूद, विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश किए गए सभी संशोधनों को ध्वनि मत से खारिज कर दिया गया। बहस के दौरान, सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने विधेयक का बचाव करते हुए दावा किया कि इसे अल्पसंख्यक समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। हालांकि, विपक्षी दलों ने इसे मुस्लिम विरोधी और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के लिए हानिकारक बताया। अपने जवाब में अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा, दुनिया में अल्पसंख्यकों के लिए भारत से ज्यादा सुरक्षित कोई जगह नहीं है। वे सुरक्षित हैं क्योंकि भारत में बहुसंख्यक पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हैं।

वक्फ (संशोधन) विधेयक को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, कई राज्य और राजनीतिक दल इसके क्रियान्वयन के खिलाफ आगे की कानूनी और लोकतांत्रिक कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं।

मोदी को लिखे पत्र में स्टालिन ने कहा, कच्चातीवु को वापस लेना मछुआरों की समस्याओं का एकमात्र समाधान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/भाषा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से पाक खाड़ी क्षेत्र में राज्य के मछुआरों के मछली पकड़ने के पारंपरिक अधिकारों की स्थायी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए श्रीलंका से कच्चातीवु द्वीप वापस लेने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया।

मोदी को लिखे पत्र में स्टालिन ने दो अप्रैल, 2025 को विधानसभा में पारित प्रस्ताव का हवाला दिया, जिसमें श्रीलंका से कच्चातीवु द्वीप को वापस लेने की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि समस्या की जड़ वर्ष 1974 में हुई भारत-श्रीलंका संधि (कच्चातीवु समझौता) है। तमिलनाडु सरकार शुरू से ही कच्चातीवु समझौते का विरोध करती आई है। तमिलनाडु के सांसदों ने 1974 में कच्चातीवु को श्रीलंका को सौंपने का संसद में कड़ा विरोध किया था। स्टालिन ने कहा हमारे मछुआरों की लगातार गिरफ्तारी और बड़ी संख्या में उनकी नावों को जब्त करने से उनका जीवन स्थायी चिंता और संकट की स्थिति में आ गया है। गिरफ्तारी और जब्ती के कारण मछुआरों की आजीविका भी अनिश्चित हो गई है। उन्होंने कहा, हमारे मछुआरों को अधिकतम कारावास की सजा दी जा रही है और उन पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। इसके अलावा, उनकी नौकाओं को जब्त करके नीलाम किया जा रहा है। श्रीलंका के इन सभी आक्रामक कदमों ने हमारे मछुआरों को अत्यधिक गरीबी के कगार पर धकेल दिया है और कच्चातीवु को पुनः प्राप्त करना इस समस्या का स्थायी समाधान खोजने का एकमात्र तरीका है।

अमित शाह इस महीने बिहार, बंगाल और तमिलनाडु का दौरा करेंगे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए इस महीने बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगे और इसके बाद उनका नियमित तौर पर इन राज्यों में जाने का कार्यक्रम है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि शाह इन राज्यों में चुनाव तक लगभग हर महीने भाजपा की संगठनात्मक बैठकें आयोजित करेंगे। उन्होंने कहा कि शाह के 14 और 15 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में तथा 30 अप्रैल को बिहार में रहने की संभावना है जबकि तमिलनाडु के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

लोकसभा में बुधवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक पर अपने हस्तक्षेप के दौरान शाह तृणमूल सदस्य कल्याण बनर्जी द्वारा राज्य की राजनीति से संबंधित कटाक्ष किए जाने के बाद आक्रामक हो गए थे। तमिलनाडु में हमेशा एक हाशिये पर रहने वाली भाजपा से उम्मीद की जा रही है कि वह राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के साथ अपने गठबंधन को पुनर्जीवित कर सकती है ताकि दक्षिणी राज्य में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेतृत्व वाले 'इंडि' गठबंधन को टक्कर दी जा सके। द्रमुक का 2021 से ही राज्य की सत्ता पर दबदबा रहा है।

अन्नाद्रमुक नेता एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने हाल ही में शाह से मुलाकात की, जिससे दोनों दलों के एक साथ आने की संभावना बढ़ गई है। तमिलनाडु विधानसभा के लिए 2021 में हुए चुनाव में अन्नाद्रमुक और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन बाद में द्रविड़ पार्टी गठबंधन से बाहर हो गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों दल अलग-अलग मैदान में उतरे, लेकिन दोनों को करारी हार का सामना करना पड़ा।

कच्चातीवु को श्रीलंका को सौंपना 'असंवैधानिक', सरकार इसे वापस लेने के लिए कदम उठाये : बालू

चेन्नई/नई दिल्ली। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) नेता टी आर बालू ने बृहस्पतिवार को कहा कि कच्चातीवु द्वीप को श्रीलंका को सौंपना ''असंवैधानिक'' है और उन्होंने केंद्र से इसे शीघ्र वापस लेने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान इस मामले को उठाते हुए बालू ने कहा कि बुधवार को तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने पेश किया था।

द्रमुक सांसद ने कहा कि प्रस्ताव के जरिये केंद्र से कच्चातीवु द्वीप को वापस लेने का आग्रह किया गया। कच्चातीवु को भारत ने 1974 और 1976 में हुए समझौतों के माध्यम से श्रीलंका को सौंप दिया था। बालू ने उच्चतम न्यायालय के एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि जब तक संसद इसे मंजूरी नहीं दे देती और इसकी पुष्टि नहीं कर देती, भूमि को नहीं सौंपा जाना चाहिए।

द्रमुक नेता ए. राजा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, 'कुमकुम मत लगाओ'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। द्रविड मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के वरिष्ठ नेता ए. राजा ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी की धोती पहनते समय 'कुमकुम' लगाने और कलावा बांधने से बचने की 'सलाह' दी है। ए. राजा ने कहा कि विचारधारा के बिना किसी राजनीतिक दल का केवल विनाश ही होगा और इसका एक उदाहरण अन्ना द्रविड मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) है।

पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजा ने कहा कि वह भगवान में आस्था रखने के विरोध में नहीं है बल्कि पार्टी के संस्थापक सी. एन. अन्नादुरई ने कहा था कि गरीबों की मुस्कान में ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं।

राजा ने कुछ दिन पहले नीलगिरि जिले में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, लेकिन जब आप पोट्टू (कुमकुम) लगाते हैं और कैइरू (कलावा) बांधते हैं और जब संघी (आरएसएस के लोग) भी ऐसा करते हैं, तो अंतर करना मुश्किल हो जाता है। उनके कथित संबोधन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। द्रमुक उप महासचिव ने कहा कि 'कम से कम छात्र शाखा से जुड़े लोगों को पोट्टू हटा देना चाहिए।' हालांकि, राजा ने यह स्पष्ट किया कि वह ईश्वर की पूजा करने से मना नहीं कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अगर उनके माता-पिता माथे पर 'विभूति' लगाते हैं, तो उन्हें इसे मानना चाहिए।

राजा द्वारा कार्यकर्ताओं से कुमकुम लगाने से बचने के लिए कहे जाने के बारे में पूछे जाने पर द्रमुक नेता और हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ निधि मंत्री पीके शेखर बाबू ने कहा कि उनकी पार्टी के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने ऐसा कुछ नहीं कहा है और ये राजा के निजी विचार है। मंत्री पीके शेखर बाबू हमेशा कुमकुम लगाते हैं। ए. राजा ने पूर्व में सनातन धर्म की तुलना एचआईवी/एड्स से करके विवाद खड़ा कर दिया था।

राजा की टिप्पणी की निंदा करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तमिलनाडु इकाई ने पूछा कि द्रमुक धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाना कब बंद करेगी। राजा पर लगातार हिंदू धर्म को तुच्छ बताने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने कहा कि द्रमुक नेता अब एक कदम आगे बढ़ गए हैं और छात्र संगठन से तिलक या कुमकुम न लगाने को कह रहे हैं।

क्या केवल हिन्दू धर्म का विरोध करने वाले ही द्रमुक का हिस्सा हो सकते हैं?

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एएनएस प्रसाद ने गुरुवार को द्रमुक के वरिष्ठ नेता ए. राजा के व्यक्तव्य की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री स्टालिन को पूर्व केंद्रीय मंत्री ए. राजा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ए. राजा हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों के बीच सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति को भड़काना जारी रखे हुए हैं। वह बार बार हिंदू धर्म और हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करने और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बावजूद द्रमुक के प्रमुख मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा उनकी निंदा क्यों नहीं की गई। ऐसाप्रतीत होता है कि द्रमुक के प्रमुख भी यह चाहते हैं क्या?

हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ निधि विभाग की देखरेख करने वाले मंत्री शेखरबाबू पर उन लोगों का समर्थन करने का आरोप लगाया गया है जो विभाग की संपत्तियों का दुरुपयोग करते हैं और हिंदू धर्म की पवित्रता को नीचा दिखाते हैं। यह अस्वीकार्य है कि वह ए. राजा की विवादास्पद टिप्पणियों को व्यक्तिगत राय बताकर मुद्दे को भटकाने की कोशिश करते हैं। ए. राजा का यह कथन कि द्रमुक सदस्यों को पोट्टू (माथे का निशान) लगाना बंद कर देना चाहिए, यह हिंदू प्रतीकों पर अप्रत्यक्ष हमला है। द्रमुक सदस्यों को पोट्टू के बिना सिर्फ़ वेष्टि नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि इससे उनके और पारंपरिक प्रथाओं को बनाए रखने वालों के बीच का अंतर धुंधला हो जाता है। कम से कम, छात्र विंग के सदस्यों को माथे के निशान हटा देने चाहिए, जैसा कि ए. राजा सुझाव देते हैं। उन्होंने मांग की कि ए. राजा, जो डीएमके के उप महासचिव और सांसद भी हैं, को हिंदू धार्मिक भावनाओं का अपमान करने वाले असंवैधानिक बयान देने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। क्या मुख्यमंत्री स्टालिन या उनके परिवार के सदस्य ए. राजा द्वारा समर्थित हिंदू विरोधी प्रचार का समर्थन करेंगे? हाल ही में ए. राजा हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक और सोची-समझी बातें कर रहे हैं। अगर वह द्रमुक के मुस्लिम और ईसाई सदस्यों के धर्मों के बारे में भी ऐसी ही अपमानजनक टिप्पणी करते, तो क्या वह तमिलनाडु में अब भी स्वतंत्र रूप से घूम पाते? हिंदू धर्म, जो अपनी सहिष्णुता और सद्भावना के लिए जाना जाता है, को ए. राजा या किसी और को और अधिक परखना नहीं चाहिए। अगर वह हिंदुओं को भड़काना और उनकी मान्यताओं को चुनौती देना जारी रखते हैं, तो वे तमिलनाडु में रहने के लिए अयोग्य हो सकते हैं।

फिल्म उद्योग को महिलाओं के अनुकूल होना चाहिए : केरल की मंत्री वीणा जॉर्ज

तिरुवनंतपुरम/भाषा। केरल सरकार में मंत्री वीणा जॉर्ज ने बृहस्पतिवार को कहा कि फिल्म उद्योग एक सुरक्षित और महिला-अनुकूल स्थान होना चाहिए तथा फिल्म निर्माण के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना निर्माता की जिम्मेदारी है।

वीणा जॉर्ज ने कहा, ''फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अधिकाधिक महिलाओं को कैमरे के सामने और पीछे दोनों जगह आगे आना चाहिए। जब कोई फिल्म बनाई जाती है, तो फिल्म निर्माण में शामिल सभी लोगों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। पॉश अधिनियम (यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम)-2013 के प्रावधानों और न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के मद्देनजर यह और भी आवश्यक है।'' राज्य की स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही। फिल्म उद्योग में काम करने वाले लोगों के बीच पॉश अधिनियम (यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम) के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए केरल के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जेंडर पार्क के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि पॉश अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल आयोजित किया गया है।

वक्फ संशोधन विधेयक मुनंबम के लोगों के संपत्ति अधिकारों के लिए अहम कदम : चंद्रशेखर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

तिरुवनंतपुरम/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केरल इकाई के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा द्वारा विवादास्पद वक्फ़ संशोधन विधेयक पारित किए जाने का स्वागत करते हुए इसे मुनंबम सहित सभी नागरिकों के लिए संपत्ति के अधिकार को बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम बताया है। चंद्रशेखर ने बृहस्पतिवार को फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि 'तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित कांग्रेस सरकारों द्वारा दशकों तक पोषित की गयी' वक्फ़ प्रणाली ने संवैधानिक अधिकारों को पूरी तरह से कुचल दिया तथा व्यक्तियों को उनकी संपत्ति के उचित स्वामित्व से वंचित कर दिया।

भाजपा नेता ने अपने पोस्ट में कहा, यह संशोधन समानता बहाल करेगा, संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करेगा, तथा देश के विभिन्न भागों में प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार अपने वादों को पूरा करने तथा सभी के लिए न्याय, निष्पक्षता और समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा ने बुधवार को विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों के कड़े विरोध के बीच और 12 घंटे से अधिक समय तक चर्चा करने के बाद देर रात करीब दो बजे वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 को पारित कर दिया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने सदन में वक्फ़ संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सरकार के इस कदम को मुस्लिम विरोधी बताने के कई विपक्षी सदस्यों के दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को मुसलमानों को बांटने वाला बताया जा रहा है, जबकि सरकार इसके जरिए शिया, सुन्नी समेत समुदाय के सभी वर्गों को एक साथ ला रही है।

रीजीजू के जवाब के बाद सदन ने अनेक विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को खारिज करते हुए 232 के मुकाबले 288 मतों से वक्फ़ (संशोधन) विधेयक-2025 को पारित किया। सदन ने मुसलमान वक्फ़ (निरसन) विधेयक-2024 को भी ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इस बीच, 'मुनंबम भू संरक्षण समिति' के बैनर तले 173 दिनों से क्रमिक भूख हड़ताल पर रहे मुनंबम के लोग बृहस्पतिवार को खुशी से झूम उठे, क्योंकि लोकसभा ने बुधवार देर रात वक्फ (संशोधन) विधेयक पारित कर दिया।

''नरेन्द्र मोदी जिंदाबाद'' जैसे नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने उम्मीद जताई कि नया कानून लागू होने के बाद यह मुद्दा सुलझ जाएगा। प्रदर्शनकारियों में अधिकतर ईसाई समुदाय के लोग हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि वे बृहस्पतिवार को जश्न मनाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन मौजूदा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।।समिति के संयोजक जोसेफ़ बेनी ने कहा कि वे बहुत खुश हैं और साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि विधेयक लागू होने पर उन्हें अपनी संपत्तियों पर राजस्व अधिकार मिल जाएगा। बेनी ने संसद में मुनंबम समुदाय की चिंताओं को आवाज देने में कथित तौर पर विफल रहने को लेकर कांग्रेस और वामपंथी दलों के सांसदों की आलोचना भी की। हालांकि, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू से मिले समर्थन को स्वीकार किया।

लोकसभा में विधेयक पारित होने के तुरंत बाद, कोच्चि के पास मुनंबम तटीय क्षेत्र के लगभग 600 परिवारों ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। लोगों को उम्मीद है कि वक्फ़ (संशोधन) विधेयक के कानून बनने के बाद उनकी जमीन पर वक्फ़ बोर्ड के दावे का मुद्दा हल हो जाएगा। राजीव चंद्रशेखर और वी. मुरलीधरन सहित भाजपा के कई नेता बृहस्पतिवार को मुनंबम का दौरा करने वाले हैं। सिरो-मालाबार चर्च ने लोकसभा द्वारा पारित वक्फ संशोधन विधेयक का स्वागत करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि इससे मुनंबम के लोगों को राहत मिलेगी।

चेन्नई पोर्ट और कामराजर पोर्ट ने हासिल कीं कई उपलब्धियां

शानदार वृद्धि के साथ जहाजों का रिकॉर्ड बनाया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। राजाजी सलाई के न्यू कॉन्फ्रेंस हॉल में चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन सुनील पालीवाल ने संवाददाताओं को संबोधित किया।

इस दौरान चेन्नई पत्तन प्राधिकरण और कामराजर पोर्ट लिमिटेड (केपीएल) के वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रचालन और वित्तीय निष्पादन से जुड़ी जानकारी साझा की गई। बताया गया कि चेन्नई पोर्ट और कामराजर पोर्ट ने पहली बार 100 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा संयुक्त कार्गो थ्रोपुट के साथ ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जो कुल 103.37 एमएमटी तक पहुंच गई है। चेन्नई पोर्ट ने 54.96 एमएमटी तथा कामराजर पोर्ट ने 48.41 एमएमटी का योगदान दिया है। यह संयुक्त रूप से वर्ष-दर-वर्ष 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। चेन्नई पोर्ट ने 6.5 प्रतिशत और कामराजर पोर्ट ने 6.9 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। चेन्नई पोर्ट ने कंटेनर हैंडलिंग में अब तक का सर्वोच्च स्तर हासिल किया, जो 1.8 मिलियन टीईयू से ज्यादा था। इस पोर्ट ने ट्रेलरों की अब तक की सबसे अधिक एकल-दिवसीय हैंडलिंग भी हासिल की, जिसमें 6,256 ट्रेलरों को संसाधित किया गया। इसी तरह, कामराजर पोर्ट ने 48.41 एमएमटी की अब तक की सबसे ज्यादा कार्गो हैंडलिंग हासिल की है। केपीएल ने मार्च 2025 के दौरान 4.58 मिलियन टन के साथ अपनी अब तक की सबसे ज्यादा मासिक कार्गो हैंडलिंग दर्ज की है। पोर्ट ने 1,110 जहाजों का रिकॉर्ड बनाया है।

इसके साथ ही चेन्नई पोर्ट और कामराजर पोर्ट, दोनों ने रिकॉर्ड प्रचालन आय हासिल की। हर पोर्ट ने 1,000 करोड़ रु. का आंकड़ा पार किया। चेन्नई पोर्ट की प्रचालन आय 1088.22 करोड़ रु. और कामराजर पोर्ट की प्रचालन आय 1130.60 करोड़ रु. थी। चेन्नई पोर्ट की क्रूज़ टर्मिनल क्षमता 1,000 यात्रियों से बढ़ाकर 1,800 यात्री की जाएगी। यहां प्रौद्योगिकी सुधार और भंडारण क्षेत्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें वीडियो वॉल, स्वदेशी वीटीएमएस, ईएक्सआईएम गोदाम और पक्के भंडारण यार्ड, आंतरिक सड़क नेटवर्क का विकास और मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क चरण-1 का संचालन शामिल है। कामराजर पोर्ट योजनाओं में उत्तरी ब्रेकवाटर का पुनर्वास, सीमा शुल्क भवन, नाविक क्लब, डीसलैनेशन संयंत्र और एकीकृत आदेश और नियंत्रण केंद्र का विकास शामिल है।

केरल उच्च न्यायालय ने 'भ्रामक' विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव के विरुद्ध कार्यवाही पर रोक लगाई

कोच्चि/भाषा। केरल उच्च न्यायालय ने योग गुरु बाबा रामदेव, उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण और उनकी कंपनी दिव्य फार्मेसी के खिलाफ ''भ्रामक'' विज्ञापन मामले में निचली अदालत में सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी। रामदेव और अन्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अजित कुमार (सस्थमंगलम) ने इस बात की पुष्टि की कि न्यायमूर्ति वी जी अरुण ने पलक्कड़ मजिस्ट्रेट अदालत में कार्यवाही पर तीन महीने के लिए रोक लगा दी है। यह अंतरिम आदेश कंपनी, रामदेव और बालकृष्ण द्वारा दायर याचिका पर जारी किया गया, जिसमें मामले में उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।

मुख्यमंत्री ने जारी की राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान को वर्ष 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और निवेश अनुकूल औद्योगिक वातावरण सुनिश्चित करने के क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी–2025 जारी की है। यह नीति राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने और कनेक्टिविटी में वृद्धि करते हुए लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाएगी और राजस्थान को लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करेगी। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि यहां लगने वाले उद्योग लॉजिस्टिक्स एवं परिचालन लागत को कम रखते हुए निर्यात के साथ–साथ स्थानीय मांग को भी बखूबी पूरा कर सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा साझा करते हुए, हमारा राज्य देश के लगभग 40 प्रतिशत बाजार तक पहुंच रखता है। यह भारत के उत्तरी और पश्चिमी भागों के बीच प्रमुख बुनियादी ढांचे की सुविधा के रूप में उद्योगों को कच्चे माल तथा तैयार उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में पूरी तरह से सक्षम है। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क और दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क राजस्थान में ही है। इसके अलावा 9 इनलैंड कंटेनर डिपो, 7 एयरपोर्ट और एक एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स हमें लॉजिस्टिक्स और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत स्थिति प्रदान कर रहे हैं। राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी–2025 राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का लाभ लेते हुए औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देगी और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाते हुए उद्योगों को भी आगे बढ़ने के भरपूर अवसर प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री शर्मा द्वारा जारी राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी–2025 में राजस्थान को लॉजिस्टिक्स के लिए पसंदीदा गंतव्य स्थल बनाने के लिए कई आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। इनमें कई तरह की विशेष छूट और अनुदान शामिल हैं। वेयरहाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, इनलैण्ड कन्टेनर डिपो, कन्टेनर फ्रेट स्टेशन, एयर फ्रेट स्टेशन, कार्गो टर्मिनल, ट्रकर पार्क इत्यादि के लिए 5 से 50 करोड़ रुपए तक इलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट (ईएफसीआई) की 25 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी दस वर्षों तक देने का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश में लॉजिस्टिक्स पार्क का विकास करने वाले निवेशकों को भी विशेष रियायतें दी गई हैं। निजी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और एकीकृत लॉजिस्टिक्स पार्क डेवलपर्स को 7 वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा, जिसकी वार्षिक सीमा 50 लाख रुपए होगी। कर एवं शुल्कों में विभिन्न रियायतें भी दी जाएंगी, जिसमें स्टाम्प ड्यूटी पर 75 प्रतिशत छूट और 25 प्रतिशत पुनर्भरण, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 7 वर्षों तक 100 प्रतिशत छूट, कन्वर्जन ऑफ लैंड चार्जेज पर 75 प्रतिशत छूट और 25 प्रतिशत पुनर्भरण तथा मंडी फीस पर 7 वर्षों तक 100 प्रतिशत छूट शामिल हैं।

राज्य सरकार ने नीति के माध्यम से युवाओं को सक्षम बनाने और उन्हें निजी क्षेत्र में रोजगार के उचित अवसर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत भी कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। इसमें दक्षता एवं प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए कार्मिक प्रशिक्षण की कुल लागत का 50 प्रतिशत पुनर्भरण (अधिकतम 4000 रुपए प्रति वर्कर प्रति माह, 6 माह तक) का प्रावधान शामिल है। तकनीकी उन्नयन के तहत ट्रक ट्रैकिंग उपकरणों की लागत पर प्रति ट्रक 2000 तक 50 प्रतिशत पुनर्भरण, लॉजिस्टिक्स प्रबंधन सॉफ्टवेयर के प्रति इंस्टॉलेशन पर 2 लाख रुपए तक 50 प्रतिशत पुनर्भरण और फायर डिटेक्शन सिस्टम की लागत पर 20 प्रतिशत (अधिकतम 10 लाख रुपए) एकमुश्त पुनर्भरण की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

राठौड़ ने धाबास में बोरवेल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बुधवार को धाबास के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय और केसर विहार में वर्षा जल संचयन के लिए बोरवेल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के मार्गदर्शन में झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कर्मभूमि से मातृभूमि, कैच द रेन अभियान के तहत 150 बोरवेल का निर्माण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य बारिश के पानी को संरक्षित करना और उसका दोबारा उपयोग करना है।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि वर्षा जल को बचाना और उसका संरक्षण करना हम सभी की जिम्मेदारी है। जल संरक्षण अब एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जन–जन की प्रेरणा बन गया है। कर्मभूमि से मातृभूमि एक अनूठी पहल है जो हमारी प्रकृति को सुरक्षित और संरक्षित रखने का प्रयास करती है।

उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान में पानी की कमी को दूर करने के लिए सरकार पूरी तरह से संकल्पित है। इसके लिए नदी से नदी जोड़ो अभियान, बोरवेल निर्माण, उच्च जलाशय का निर्माण और सड़क निर्माण जैसे विकास कार्य इंटीग्रेटेड प्लानिंग के तहत किए जा रहे हैं।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने सभी से गांवों में उपलब्ध कुएं, तालाब, बावड़ी और नदियों के संरक्षण के लिए सहभागिता से काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर इस पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि झोटवाड़ा के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि झोटवाड़ा को एक हरा–भरा और खुशहाल विधानसभा क्षेत्र बनाने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं।

विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए डिस्कॉम्स उठाएं प्रभावी कदम : भजनलाल शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गर्मी के मौसम में आमजन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि डिस्कॉम्स के अधिकारी बिजली आपूर्ति की सतत मॉनिटरिंग करें और लाइनों में सुधार, ट्रांसफार्मर और जीएसएस स्थापित करने से संबंधित कार्यों को समय पर पूरा करें। साथ ही, डिस्कॉम्स बिजली छीजत घटाने को प्राथमिकता देते हुए इसे न्यूनतम करने का लक्ष्य प्राप्त करें।

शर्मा मुख्यमंत्री निवास पर जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगमों (डिस्कॉम्स) की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डिस्कॉम्स उन ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करें, जहां गत वर्ष विद्युत आपूर्ति सुचारू नहीं थी। टीएण्डडी और एटीएण्डसी लॉसेज को न्यूनतम करने के लिए फीडर्स लेवल मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही, खराब मीटर्स का रिपेयर और रिप्लेसमेंट सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ऊर्जा उत्पादन निगम को पीक टाइम से पहले मेंटेनेंस पूरा करने के लिए भी निर्देशित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम कुसुम) ए तथा सी कम्पोनेन्ट्स मील का पत्थर साबित होंगे।

इन कम्पोनेंट में अपेक्षित गति लायी जाए। उन्होंने कहा कि विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण में आरडीएसएस योजना की अहम भूमिका है। इस योजना की प्रभावी क्रियान्विति से घरेलू एवं अघरेलू उपभोक्ताओं को सुचारू बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी और उन्हें ट्रिपिंग की समस्या से भी निजात मिलेगी। जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम्स इस योजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करें। जो कॉन्ट्रेक्टर्स योजना के कार्यों को संपादित करने में अनावश्यक देरी कर रहे हैं, उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को सोलर प्लांट लगाते हुए निःशुल्क 150 यूनिट्स बिजली प्रतिमाह उपलब्ध कराएगी। जिन अल्प आय वर्ग के घरों पर सोलर प्लांट का स्थान उपलब्ध नहीं है, वहां पर सामुदायिक सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस योजना की त्वरित क्रियान्विति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

जयपुर जिला कलेक्टर कार्यालय में बम विस्फोट की धमकी 'फर्जी' निकली : अधिकारी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। जयपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर (कलेक्ट्रेट) में बम विस्फोट करने की धमकी बृहस्पतिवार को जांच के बाद 'फर्जी' पाई गई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ईमेल पर इस बारे में धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने परिसर की गहन तलाशी ली। उन्होंने बताया कि बम निरोधक दस्ते, श्वान दस्ते और अन्य विशेषज्ञों की टीम ने लगभग दो घंटे तक पूरे भवन की गहनता से जांच की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।

पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अमित बुडानिया ने बताया कि आज जयपुर जिलाधिकारी कार्यालय को ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें कलेक्ट्रेट में बम विस्फोट करने की धमकी दी गई। उन्होंने बताया कि प्रशासन और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कलेक्टर कार्यालय परिसर को खाली करा लिया और लोगों का प्रवेश रोक दिया। बुडानिया ने बताया कि जांच टीमों को बुलाकर भवन के हर कमरे और हिस्से की जांच की गई तथा चार टीमों ने गहन तलाशी ली और करीब दो घंटे बाद कर्मचारियों और लोगों का प्रवेश शुरू हुआ।

कलेक्टर कार्यालय परिसर के पास ही जिला अदालत व मिनी सचिवालय है। ईमेल मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गई और सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ–साथ अन्य लोगों को परिसर से बाहर जाने को कहा गया। परिसर को खाली कराने के बाद गहन जांच की गई। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि विशेषज्ञों की टीम ईमेल भेजने वाले की पहचान करने और उसका पता लगाने की कोशिश कर रही है।

कोटा संभाग में हल्की बारिश

जयपुर/दक्षिण भारत। राजस्थान के कोटा संभाग में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से हल्की बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी। आईएमडी के जयपुर केंद्र के अनुसार बृहस्पतिवार सुबह 24 घंटे की अवधि में राज्य के कोटा संभाग में कहीं–कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश हुई जबकि शेष राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक बारिश खानपुर, झालावाड़ में दो मिलीमीटर हुई। वहीं, कल राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 40.7 डिग्री सेल्सियस व निम्नतम न्यूनतम तापमान अलवर में 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

इसके अनुसार पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से पूर्वी व दक्षिण–पूर्वी राजस्थान में बादल छाए रहने की संभावना है। आज जयपुर, भरतपुर व कोटा संभाग में मेघ गर्जन के साथ कहीं–कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं–कहीं अचानक 40–50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

ईश्वरानंद ब्रह्मचारी उत्तम स्वामी का देवनानी ने आशीर्वाद लिया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरूवार को चैत्र नवरात्रा के अवसर पर यहां अनंत विभूषित महामंडलेश्वर श्री1008 ईश्वरानंद ब्रह्मचारी उत्तम स्वामी को माला और दुपट्टा पहनाकर आशीर्वाद लिया। देवनानी ने कहा कि स्वामीजी के दर्शन से अध्यात्मिक ऊर्जा, शांति एवं सकारात्मकता की अनुभूति होती है। उनके मार्गदर्शन से भक्ति और सेवा के महत्व को समझने का लोगों को अवसर प्राप्त हो रहा है। स्वामी के आध्यात्मिक प्रवचनों से सकारात्मक वातावरण का निर्माण हो सकेगा।

विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने स्वामी को राजस्थान विधान सभा का साहित्य भेंट किया। देवनानी ने स्वामी को राजस्थान विधान सभा में नवाचारों का एक वर्ष पुस्तक की प्रति भी भेंट की। स्वामी ने देवनानी को विधान सभा के सदन और भवन में किये गये नवाचारों के लिये बधाई और शुभकामनायें देते हुये इन्हें राज्य के उत्तरोत्तर विकास में अग्रणी कदम बताया। देवनानी ने स्वामी से सनातन संस्कृति और आध्यत्म पर विस्तार से चर्चा की।

बड़े उद्योगपतियों की सपंत्ति बचाने ला रहे वक्फ संशोधन बिल : डोटासरा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा ने मोदी सरकार पर जुबानी हमला बोला है। डोटासरा ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि वक्फ संशोधन बिल देश में बड़े उद्योगपतियों के लिए लाया जा रहा हैं, ताकि उनकी संपत्तियां जो वक्फ प्रोपर्टी पर बनी हैं, उनको नुकसान न हो। यह कॉम्पलेक्स जो बना रखे है, उनको उसे वक्फ की संपत्ति से अलग करने के लिए बिल लाया जा रहा है। इस बिल की जरूरत क्या है, इसके उद्देश्य और कारण तो बता नहीं रहे। यह मनमानी तरीके से बिल लाकर के अधिकार लेना चाहते है, ताकि वक्फ की जो जमीन है उसको दूसरे किसी का स्वामी बन सकते हैं और इसके माध्यम से हिंदू मुस्लिम भी हो जाएगा।

इससे भाजपा की राजनीतिक रोटियां सिक जाएंगी और जिनको जमीन देनी है, उनको ये जमीनें दे देंगे। वक्फ कानून पहले से बना हुआ था, जिसके कारण संपत्तियां सुरक्षित थी।

वक्फ की कीमती संपत्ति अपने निजी लोगों को लुटाने के लिए इस प्रकार के कानून में संशोधन हो रहे हैं। ये लोग झूठ बोलते है, कि हमारी संसद को भी कल को वक्फ संपत्ति घोषित कर देंगे। पहले की संसद बढ़िया थी, जिसे इन्होंने बेकार कर दिया। दूसरी संसद बीस हजार करोड़ लगाकर बनाकर अपनी मनमर्जी से कानून बना दिए, ताकि हिंदू मुस्लिम का भी माहौल बन जाए और धार्मिक ध्रुवीकरण भी हो जाए।

जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने वाला कानून लाया गया : गहलोत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और रुपये के अवमूल्यन जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को निशाने पर लाने वाला कानून बनाने का आरोप लगाया। वक्फ संशोधन विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ को लेकर किसी नए कानून की कोई जरूरत नहीं थी और यह कदम अल्पसंख्यक वर्ग में भय पैदा करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि भारत सरकार महंगाई, बेरोजगारी, शेयर बाजार में आ रही गिरावट, रुपये के अवमूल्यन जैसे जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बार–बार अल्पसंख्यक वर्ग को निशाने पर लेने वाले कानून बनाती है। गहलोत ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, पूर्व में नागरिक (संशोधन) कानून (सीएए) के दौरान भी ऐसा देखा गया क्योंकि कानून 2020 में ही बना दिया पर इसके नियम 2024 में बनाए गए लेकिन इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए बार–बार इस मुद्दे को उछाला गया और पूरे देश में तनाव पैदा किया गया। कांग्रेस नेता कहा, वक्फ को लेकर बनाया गया कानून भी इसी का हिस्सा है। वक्फ को लेकर किसी नए कानून की आवश्यकता नहीं थी पर बहुसंख्यक वर्ग का जरूरी विषयों से ध्यान हटाने और अल्पसंख्यक वर्ग में भय पैदा करने तथा दोनों वर्गों के बीच तनाव पैदा करने के लिए यह कानून बनाया गया है।

द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 25 के माध्यम से राजस्थान और जयपुर में आईफा जैसे आयोजनों के लिए बनेंगी संभावनाएं : दीया कुमारी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी अध्यक्षता में पर्यटन विभाग की ओर से 4 से 6 मई तक जयपुर में होने वाले 14वें द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 25 (जीआईटीबी) के सम्बन्ध गुरुवार को शासन सचिवालय में बैठक आयोजित की गई। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बैठक में निर्देश दिए की राजस्थान और भारत को एम.आई.सी.ई. (बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियाँ) (चशशींळपसी, खपलशपींळींशी, उेपषशीशपलशी, रपव एहळलळींळेपी) के लिए अग्रणी गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करने के आयोजित होने वाली इवेंट जीआईटीबी को सफलता पूर्वक आयोजित करने के लिए आवश्यक तैयारी की जाए। उन्होंने कहा कि जयपुर में आईफा जैसे भव्य आयोजन सफलता पूर्वक किये जाने के बाद जीआईटीबी का आयोजन बेहतरीन हो। जिससे आईफा जैसे अन्य बड़े राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय इवेंट आयोजित होने की इस इवेंट के माध्यम से सम्भावनाएं प्रबल हो सके।

महानिदेशक पर्यटन, भारत सरकार मुग्धा सिन्हा ने बैठक में जीआईटीबी के आयोजन से सम्बंधित प्रस्तुतिकरण देते हुए बताया कि ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाज़ार (जीआईटीबी) 2008 में अपनी स्थापना के बाद से 13 वर्षों से जयपुर, राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। महानिदेशक पर्यटन, भारत सरकार ने बताया कि जीआईटीबी एक अखिल भारतीय, विशिष्ट इन–बाउंड पर्यटन मंच है, जिसे पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार (मेजबान राज्य), पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। उन्होंने बताया कि जीआईटीबी को राजस्थान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (आरएटीओ), इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन (आईएचएचए), होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (एचआरएआर) का समर्थन प्राप्त है। 2008 से अब तक ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाज़ार के पिछले 13 संस्करणों में 99 देशों के लगभग 3000 अग्रणी विदेशी टूर ऑपरेटरों ने विदेशी खरीदारों के रूप में भाग लिया है।

मुग्धा सिन्हा ने बताया कि जीआईटीबी का 14वां संस्करण 4–6 मई, 2025 को जयपुर, राजस्थान में आयोजित किया जाएगा।राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री, राजस्थान के माननीय उप मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्य सचिव, पर्यटन सचिव, भारत सरकार और महानिदेशक पर्यटन, भारत सरकार को जीआईटीबी 2025 के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विदेशी खरीदारों के रूप में 280 विदेशी टूर ऑपरेटरों की उपस्थितिपूरे भारत में राज्य सरकारें और पर्यटन उद्योग विक्रेता के रूप में प्रदर्शन करेंगे। क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच 11000 से अधिक विशिष्ट पूर्व–निर्धारित बी2बी बैठकें आयोजित की जाएंगी।

उन्होंने यह भी बताया कि जीआईटीबी के दौरान राजस्थानी व्यंजन, कला और शिल्प का प्रदर्शन। वर्ष 2023 में, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के नेतृत्व में जी–20 पर्यटन एक्सपो 2023 का आयोजन जीआईटीबी 2023 के साथ किया गया। वर्ष 2024 में, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के नेतृत्व में जीआईटीबी 2024 के साथ वेड इन इंडिया एक्सपो का आयोजन किया गया। महानिदेशक पर्यटन, भारत सरकार ने बताया कि एक्सपो का उद्देश्य राजस्थान और भारत को अग्रणी विवाह पर्यटन स्थल के रूप में प्रदर्शित करना था।वर्ष 2025 में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की अगुवाई में मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन जीआईटीबी 2025 के साथ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कॉन्क्लेव का उद्देश्य राजस्थान और भारत को एम.आई.सी.ई. के लिए अग्रणी गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करना है।

आंदोलनकारी श्रमिकों ने कारखाने में तोड़फोड़ की, पुलिस पर पथराव

जयपुर/दक्षिण भारत । राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक कारखाने के मजदूरों द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन बृहस्पतिवार को हिंसक हो गया। आंदोलनकारी मजदूरों ने कारखाने में तोड़फोड़ की और पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने यह जानकारी दी। घटना चित्तौड़गढ़ रोड पर स्थित कपड़ा कारखाने में हुई, जहां मजदूर दिवाली बोनस की मांग कर रहे थे और आज हिंसक हो गए। पुलिस ने बताया कि धरना दे रहे मजदूरों ने कारखाने में तोड़फोड़ शुरू कर दी। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया तो पुलिस ने उन्हें तितर–बितर करने के लिए बल प्रयोग किया। क्षेत्राधिकारी श्याम सुंदर जोशी, हमीरगढ़ के थानाधिकारी संजय गुर्जर और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद थे। मजदूर संघ के प्रतिनिधि देवेंद्र वैष्णव ने कहा कि मजदूर दिवाली बोनस की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कई दौर की बातचीत के बावजूद इस मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई। कारखाना प्रबंधन मुद्दों को सुलझाने के लिए गंभीर नहीं था, जिसके कारण आज मजदूरों को धरने पर बैठना पड़ा। पुलिस ने घटना के सिलसिले में सात लोगों को हिरासत में लिया है।

इस बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भीलवाड़ा की कपड़ा फैक्टरी में पुलिस पर हमला और गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने कहा, कपड़ा फैक्टरी के मजदूरों द्वारा बोनस की मांग को लेकर हुए विवाद का हिंसक रूप ले लेना और पुलिस पर हमला करना प्रदेश की कानून–व्यवस्था के लिए अत्यंत चिंताजनक है। भाजपा सरकार के 15 महीनों के जंगलराज में प्रदेश में ये हाल हो गए की आजकल हर दिन कानून के रखवालों पर ही हमले हो रहे है। रोजाना पुलिस पर हमले होना प्रशासनिक लापरवाही और सरकार की उदासीनता हैं।

रामनवमी का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, यह सुनिश्चित करे पश्चिम बंगाल सरकार : राज्यपाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने तृणमूल कांग्रेस सरकार को निर्देश दिया है कि वह राज्य में रामनवमी का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाना सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम उठाए। एक बयान में बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी गई।

बोस ने सरकार को किसी भी अप्रिय घटना रोकने के लिए पर्याप्त बल तैनात करने का भी निर्देश दिया। राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्सव में किसी भी तरह से बाधा न आए, राज्यपाल ने राज्य सरकार को सख्त सलाह दी है कि वह पूरे राज्य में रामनवमी शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए।'' इसमें कहा गया है, ''राज्य सरकार को यह सलाह भी दी गई है कि वह राज्य के किसी भी हिस्से में किसी भी अप्रिय घटना के बारे में राजभवन को तत्काल सूचित करे।'' रामनवमी छह अप्रैल को मनाई जाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के सभी समुदायों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान दिए बिना रामनवमी का त्योहार शांतिपूर्वक मनाएं। भाजपा पर स्पष्ट रूप से निशाना साधते हुए बनर्जी ने इसे एक जुमला संगठन बताया आर कहा कि इसका एकमात्र एजेंडा देश को धर्म के आधार पर बांटना है। बनर्जी ने राज्य सचिवालय में कहा, मैं सभी समुदायों से रामनवमी के दौरान शांति बनाए रखने, अफवाहों पर ध्यान न देने और सतर्क रहने की अपील करती हूं।

उप्र के मुख्यमंत्री योगी ने वक्फ बोर्ड पर भूमि अतिक्रमण करने का आरोप लगाया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

प्रयागराज/भाषा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड पर बृहस्पतिवार को सीधा हमला करते हुए इस पर भूमि अतिक्रमण करने का आरोप लगाया और इस बात पर जोर दिया कि सार्वजनिक और ऐतिहासिक स्थलों पर इसका मनमाना दावा ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

यहां शृंगवेरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ''आप यहां निषादराज की पौराणिक भूमि पर कब्जा देख रहे हैं ना। शहर में जगह-जगह वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। यहां तक की कुंभ के समय भी बयान दिए गए कि कुंभ की भूमि भी वक्फ की है। हमने पूछा था- क्या वक्फ बोर्ड भू-माफिया बन गया है।''

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार के तहत इस तरह के अतिक्रमण हटा दिए गए हैं और माफियाओं को उत्तर प्रदेश से बाहर खदेड़ दिया गया है। उन्होंने कहा, ''निषाद राज से जुड़ी पवित्र भूमि समेत कई जगहों पर वक्फ के नाम पर अतिक्रमण किया गया। लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। उनकी आपत्तियों के बावजूद भव्य और दिव्य कुंभ मेले का आयोजन किया गया।''

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड की कथित अनियमितताओं के खिलाफ विधायी कार्रवाई करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी सराहना की।

उन्होंने कहा, ''हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आभारी हैं कि उन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाई है। इस मुद्दे को हल करने वाला एक महत्वपूर्ण विधेयक पहले ही लोकसभा में पारित हो चुका है और अब इसे राज्यसभा में भी पारित किया जाएगा।''

वक्फ (संशोधन) विधेयक बुधवार को लोकसभा में पारित हो गया और बृहस्पतिवार को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य अब अवैध दावों को बर्दाश्त नहीं करेगा और राष्ट्रीय हित को पहले स्थान पर रखना होगा। उन्होंने कहा, ''जो लोग राष्ट्र के प्रति वफादार हैं, वे हमेशा अपना रास्ता खोज लेंगे।''

वक्फ विधेयक का मकसद पारदर्शिता सुनिश्चित करना और जवाबदेही तय करना : नड्डा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक का मकसद वक्फ की जमीन के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है ताकि उनके दुरुपयोग पर काबू पाया जा सके और 'मलाई खाने' वाले जमीन माफिया पर रोक लग सके। उन्होंने कहा कि यह विधेयक राष्ट्र के हित में है और किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है और न ही किसी वोट बैंक को ध्यान में रखकर इसे लाया गया है।

राज्यसभा में वक्फ़ संशोधन विधेयक, 2025 पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए नड्डा ने कहा कि मौजूदा वक्फ कानून से मुसलमानों को नुकसान हो रहा था और जमीन माफिया मलाई खा रहे थे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उसे ऐसे ''मलाई खोरों'' से दूर रहने को कहा। उन्होंने कहा कि वक्फ विधेयक राष्ट्रहित में है लेकिन विपक्ष मुद्दे को भटकाने और गलत विमर्श बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का मुख्य मकसद वक्फ की संपत्ति का उचित प्रबंधन और जवाबदेही तय करना है। सदन के नेता नड्डा ने विपक्ष के इस आरोप को खारिज कर दिया कि मोदी सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं कर रही है तथा इस विधेयक पर और विचार किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 2013 में तत्कालीन संप्रग सरकार के दौरान वक्फ संबंधी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में कुल 13 सदस्य थे जबकि इस सरकार के दौरान गठित जेपीसी में 31 सदस्य थे। उन्होंने कहा कि जगदंबिका पाल नीत जेपीसी ने व्यापक विचार किया और कुल 36 बैठकों में 200 से अधिक घंटे तक चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस जेपीसी ने 284 पक्षों से बात की जबकि पिछली जेपीसी ने 18 पक्षों से बात की थी। उन्होंने कहा कि पिछली जेपीसी ने सरसरी तौर पर चर्चा की थी जबकि इस जेपीसी ने गहराई से चर्चा की।

एफएमआर बाधित करने की योजना नहीं, प्रतिबंध अवैध गतिविधि रोकने के लिए : वीके सिंह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

आइजोल/भाषा। मिजोरम के राज्यपाल वी के सिंह ने कहा है कि भारत-म्यांमा सीमा पर मुक्त आवागमन व्यवस्था (एफएमआर) को 'बाधित' करने की कोई योजना नहीं है, लेकिन पड़ोसी देश की स्थिति के कारण सीमा पार अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं।

एक बयान में कहा गया कि सिंह ने बुधवार को दक्षिणी मिजोरम के लांगतलाई जिले के अपने पहले दौरे में विधायकों, जिला और ग्राम परिषदों के सदस्यों, अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

सिंह ने कहा, एफएमआर काफी समय से लागू है और इसे बाधित करने की कोई योजना नहीं है लेकिन पड़ोसी देश में मौजूदा अस्थिरता के कारण गांवों और नागरिकों दोनों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ सीमा पार से अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि नये उपायों का उद्देश्य कठिनाइयां पैदा करना नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा और कल्याण को बढ़ाना है।

सिंह ने भारत-म्यांमा सीमा पर बढ़ती मादक पदार्थों की तस्करी पर चिंता व्यक्त की और मिजोरम में शांति व स्थिरता बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास का आह्वान किया। उन्होंने लोगों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।

जद (यू), तेदेपा ने वक्फ विधेयक पर भाजपा के साथ मिलकर काम किया : दीपांकर भट्टाचार्य

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। भाकपा (माले) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि केंद्र में सत्तारूढ़ राजग के सहयोगी दलों जनता दल (यूनाइटेड) और तेदेपा ने वक्फ (संशोधन) विधेयक पर भाजपा के साथ मिलकर काम किया।

वामपंथी नेता ने आरोप लगाया कि विवादास्पद विधेयक ''मुस्लिम समुदाय की पहचान, धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक स्वायत्तता के लिए एक बड़ा झटका है।'' वक्फ (संशोधन) विधेयक 12 घंटे की लंबी बहस के बाद लोकसभा में पारित हो गया।

भट्टाचार्य ने फोन पर 'पीटीआई-भाषा' से कहा, ''अल्पसंख्यकों के अधिकार अंबेडकर के लोकतांत्रिक गणराज्य के विचार के केंद्र में हैं। जद (यू) और तेदेपा जैसे दल वास्तव में इस संविधान विरोधी साजिश में शामिल हैं, जिन्होंने अल्पसंख्यक अधिकारों पर हमले में भाजपा के साथ सहयोग किया है। वे बेनकाब हो चुके हैं और लोगों द्वारा उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा।''

भाजपा, जिसके पास लोकसभा में बहुमत नहीं है, सत्ता में बने रहने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जद (यू) और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू नीत तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के समर्थन पर निर्भर है।

वक्फ बोर्ड कुछ लोगों की 'जागीर' बन गया था : केशव मौर्य

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कौशांबी (उप्र)/भाषा। राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बृहस्पतिवार को कहा कि वक्फ बोर्ड कुछ लोगों की 'जागीर' बन गया था।

अपने गृह जनपद कौशांबी में नवरात्रि के अवसर पर शीतला माता का दर्शन पूजन करने के बाद मां शीतला अतिथि गृह में पत्रकारों से बातचीत में मौर्य ने कहा कि वर्तमान में वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है तथा नए कानून के तहत जमीन को जांच के बाद ही वक्फ की संपत्ति माना जाएगा और वक्फ बोर्ड की जमीनों की जांच जिला कलेक्टर की निगरानी में होगी।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा इस कानून (वक्फ संशोधन विधेयक) का विरोध मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता चाहने वाले लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और यह कानून 90 प्रतिशत गरीब मुसलमानों के हित में है।

मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अनुच्छेद 370, राम मंदिर और तीन तलाक रोधी कानून का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अनुच्छेद को 370 हटाया, राम मंदिर का निर्माण करवाया और मुस्लिम महिलाओं के हित में तीन तलाक कानून बनाया।

देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सुव्यवस्थित तरीके से हमले हो रहे हैं : कांग्रेस सांसद

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। लोकसभा में बृहस्पतिवार को कांग्रेस के एक सांसद ने आरोप लगाया कि देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सुव्यवस्थित तरीके से हमले हो रहे हैं और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है।

सदन में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस सांसद के. सी. वेणुगोपाल ने कहा कि जहां कहीं भी कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ, या भाजपा के खिलाफ बोलता है वह खतरे में पड़ जाता है। उन्होंने कहा, ''संघ परिवार और भाजपा से जुड़ी संस्थाएं उसके पीछे पड़ जाती हैं। इस तरह से हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला जा रहा है।'' उन्होंने देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुव्यस्थित तरीके से कम किये जाने का आरोप लगाते हुए कहा, ''चाहे यह मीडिया, सोशल मीडिया या फिल्म हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सुव्यवस्थित तरीके से हमले हो रहे हैं।'' उन्होंने हाल में रिलीज मलयालम फिल्म 'एल2: एम्पुरान' का उल्लेख करते हुए कहा कि केरल में, कुछ दिन से फिल्मों को निशाना बनाये जाने की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा, ''इस फिल्म को निशाना बनाया जा रहा है। यह क्यों हो रहा है, जबकि इस फिल्म को सेंसर बोर्ड का प्रमाणन मिला है। सेंसर बोर्ड में भाजपा के लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने फिल्म को मंजूरी दी। इसके बाद, फिल्म का प्रदर्शन शुरू हुआ लेकिन फिल्म के कलाकारों, निर्माताओं, निर्देशकों पर सुव्यवस्थित तरीके से हमला किया गया। अब, वे फिल्म के 24 हिस्से को काटने के लिए मजबूर हो गए...।''

अमेरिकी टैरिफ, चीन के अतिक्रमण पर क्या करेगी सरकार: राहुल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 26 प्रतिशत जवाबी शुल्क (टैरिफ) लगाये जाने का मुद्दा बृहस्पतिवार को लोकसभा में उठाया और सरकार से सवाल किया कि इसे लेकर वह क्या करने जा रही है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने सदन में शून्यकाल के दौरान, चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण करने का दावा करते हुए यह भी कहा कि इस पड़ोसी देश के साथ संबंध सामान्य होने चाहिए, लेकिन उससे पहले सीमा पर पूर्व की स्थिति बहाल होनी चाहिए और भारत की भूमि लौटाई जानी चाहिए। राहुल ने कहा, ''हमारे साझेदार देश (अमेरिका) ने 26 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है जो हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा, हमारा ऑटो उद्योग, दवा उद्योग और कृषि सभी कतार में हैं।'' उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि वह क्या करने जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 26 प्रतिशत का 'रियायती जवाबी शुल्क' लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस के रोज गार्डन से विभिन्न देशों पर शुल्क लगाने की घोषणा करते हुए कहा था, ''भारत हमसे 52 प्रतिशत शुल्क लेता है, इसलिए हम उनसे इसका आधा, 26 प्रतिशत शुल्क लेंगे।''

राहुल ने चीन के अतिक्रमण का उल्लेख करते हुए दावा किया, ''यह सर्वविदित है कि चीन हमारे 4,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर बैठा हुआ है। कुछ समय पहले मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि विदेश सचिव चीन के राजदूत के साथ केक काट रहे हैं।''

उन्होंने आरोप लगाया, ''चीन ने हमारा 4,000 वर्ग किमी क्षेत्र ले लिया, हमारे 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन केक काटकर उनकी शहादत का जश्न मनाया जा रहा है।''

वक्फ़ (संशोधन) विधेयक 2025 समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाएगा : विपक्ष ने कहा राज्य सभा में

नई दिल्ली/भाषा। वक्फ़ (संशोधन) विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने सरकार से देश में धर्म निरपेक्ष माहौल बनाने की अपील करते हुए कहा कि देश में गरीबी से लेकर और भी कई समस्याएं हैं जिनके खिलाफ जंग जरूरी है और यह विधेयक समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाएगा। विपक्षी सदस्यों ने वक्फ़ (संशोधन) विधेयक 2025 को संविधान विरोधी बताते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की।

उच्च सदन में वक्फ़ संशोधन विधेयक, 2025 पर चर्चा में भाग लेते हुए आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि सरकार वक्फ़ (संशोधन) विधेयक 2025 के माध्यम से बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पर आघात कर रही है। सरकार कहती है यह कानून मुसलमानों के भले के लिए है जबकि संसद के दोनों सदनों में सत्ताधारी दल का केवल एक मुसलमान सदस्य है और मंत्रिमंडल में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। सिंह ने इस विधेयक को ''धार्मिक संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश'' करार देते हुए कहा कि धीरे धीरे दूसरे धर्मों की संपत्ति भी इसी तरह कब्जा की जाएगी।

सिंह ने नक्सल विरोधी अभियान में जान गंवाने वाले जवान के परिवार से मुलाकात की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक (डीजी) ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान जान गंवाने वाले जवान के परिजनों से पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में बृहस्पतिवार को मुलाकात की। सिंह पश्चिम बंगाल के एक दिवसीय दौरे पर हैं।

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में 22 मार्च को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान एक आईईडी विस्फोट में उप निरीक्षक सुनील कुमार मंडल (56) की मौत हो गई थी। सीआरपीएफ के प्रवक्ता एम दिनाकरन ने दिल्ली में कहा, ''कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहूति देने वाले हमारे बहादुर जवान के माता-पिता, पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों से डीजी ने मुलाकात की। उन्होंने परिवार को हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया और कहा कि बल आज ही नहीं, बल्कि हमेशा परिवार के साथ खड़ा रहेगा।'' कोलकाता में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सीआरपीएफ महानिदेशक ने बल के अधिकारियों को मंडल के परिजनों के संपर्क में रहने और उनकी सभी जरूरतों का ध्यान रखने के निर्देश दिए। सिंह विशेष रूप से गछूपरा गांव में मंडल के परिजनों से मिलने के लिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर आए। पिछले महीने उन्होंने झारखंड में एक हेड कांस्टेबल के घर का दौरा किया था, जो फरवरी में छत्तीसगढ़ में आईईडी विस्फोट में मारा गया था।

वक्फ़ विधेयक असंवैधानिक और अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ : तृणमूल

नई दिल्ली/भाषा। राज्यसभा में बृहस्पतिवार को तृणमूल कांग्रेस ने वक्फ़ संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और दावा किया कि यह विधेयक संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने के साथ ही राज्यों के अधिकारों को भी प्रभावित करता है। उच्च सदन में वक्फ़ संशोधन विधेयक, 2025 पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस सदस्य मोहम्मद नदीमुल हक ने कहा कि यह विधेयक सिर्फ मुसलमानों से ही नहीं बल्कि पूरे देश से जुड़ा है और यह मौलिक अधिकारों का हनन भी करता है। उन्होंने इस विधेयक को गैर-जरूरी कदम बताया और कहा कि यह असंवैधानिक और अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ है। हक ने कहा कि संविधान कोई किताब नहीं बल्कि देश को रास्ता दिखाने वाला है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक संघवाद की भावना के खिलाफ भी है और इसमें सुधारों के नाम पर परंपराओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के जरिए राज्यों के अधिकारी छीने जा रहे हैं।

निजी कारणों से आईपीएल छोड़कर स्वदेश लौटे कैगिसो रबाडा

नई दिल्ली/भाषा। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा निजी कारणों से आईपीएल छोड़कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। उनकी टीम गुजरात टाइटंस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। टाइटंस ने यह नहीं बताया कि रबाडा कब तक लौटेंगे। अभी तक उन्होंने दो ही मैच खेले हैं। गुजरात टीम ने एक बयान में कहा ,'' कैगिसो रबाडा कुछ महत्वपूर्ण निजी मसले से निपटने के लिये दक्षिण अफ्रीका लौट गए हैं।'' रबाडा ने पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक एक विकेट लिया था। उन्हें बेंगलूरु के खिलाफ बुधवार को बेंगलूरु में खेले गए मैच में टीम में जगह नहीं दी गई। रबाडा की जगह अरशद खान को उतारा गया जिन्होंने कोहली का कीमती विकेट लिया।

शिक्षक भर्ती पर न्यायालय के फैसले को स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन इसका पालन करूंगी : ममता बनर्जी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह न्यायपालिका का बहुत सम्मान करती हैं, लेकिन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियों को अमान्य करार देने संबंधी उच्चतम न्यायालय के फैसले को वह स्वीकार नहीं कर सकतीं। शीर्ष अदालत ने राज्य संचालित विद्यालयों के 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध करार दिया है।

बनर्जी ने राज्य सचिवालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनकी सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले का पालन करेगी, यद्यपि अन्य कानूनी विकल्पों पर भी विचार कर रही है। उन्होंने कहा, ''मैं न्यायपालिका और न्यायाधीशों का बहुत सम्मान करती हूं, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से मैं इस फैसले को स्वीकार नहीं कर सकती।'' मुख्यमंत्री ने कहा, ''इस देश के नागरिक के रूप में मुझे अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। मैं न्यायाधीश और न्यायपालिका का सम्मान करती हूं, लेकिन मैं फैसले से सहमत नहीं हो सकती।'' प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने नियुक्तियों को रद्द करने संबंधी कलकत्ता उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल 2024 के फैसले को बरकरार रखते हुए तृणमूल सरकार को नये सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। बनर्जी ने कहा, ''हमें फैसले को स्वीकार करना होगा और कानूनी रूप से जो भी संभव होगा वह किया जाएगा।'' उन्होंने कहा, ''एसएससी (स्कूल सेवा आयोग) एक स्वायत्त निकाय है। हम, राज्य सरकार के रूप में, उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम अदालत के फैसले का पालन करेंगे।''

कुछ मैचों में कम स्कोर के आधार पर रोहित शर्मा का आकलन नहीं करें : कोच पोलार्ड

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजी कोच कीरोन पोलार्ड ने आईपीएल 2025 में रोहित शर्मा की औसत शुरूआत को तूल नहीं देते हुए कहा कि कुछ मैचों में कम स्कोर के आधार पर इस दिग्गज बल्लेबाज का आकलन नहीं किया जाना चाहिये । मुंबई इंडियंस को पांच आईपीएल खिताब दिलाने वाले पूर्व कप्तान रोहित ने अब तक तीन मैचों में 0 ,8 और 13 रन बनाये हैं ।

पोलार्ड ने लखनऊ सुपर जाइंट्स के खिलाफ शुक्रवार को होने वाले मैच से पहले कहा ,'' रोहित का नाम इतिहास में, रिकॉर्ड पुस्तिका में दर्ज है । वह खेल का लीजेंड है । कुछ मैचों में कम स्कोर के आधार पर उसका आकलन नहीं होना चाहिये ।'' पोलार्ड ने कहा कि

वह जल्दी ही बड़ी पारी खेलेंगे लेकिन उन पर दबाव नहीं बनाया जाना चाहिये । उन्होंने कहा ,'' कई बार आप रन नहीं बना पाते । एक खिलाड़ी के तौर पर वह अपने खेल का मजा ले रहा है और उस पर दबाव नहीं बनाया जाना चाहिये ।'' उन्होंने कहा ,'' मुझे यकीन है कि वह एक बड़ी पारी खेलेगा और हम उसकी तारीफों के पुल बांधते दिखेंगे । फिर हम किसी नये गर्म मुद्दे पर बात करेंगे ।''

लखनऊ सुपर जाइंट्स के मेंटोर जहीर खान ने पंजाब किंग्स के हाथों मिली हार के बाद पिच की आलोचना की थी लेकिन पोलार्ड पिच की बहस में नहीं पड़ना चाहते । उन्होंने कहा ,'' मैं क्यूरेटर नहीं हूं लेकिन हमारा मानना है कि हालात जो भी हों, उसके अनुकूल ढलना होता है । आपको हर तरह के हालात में खेलना आना चाहिये ।'' उन्होंने कहा ,'' पिचों की प्रकृति हमारे नियंत्रण में नहीं है । आप हर तरह के हालात में अच्छा खेलकर ही विश्व स्तरीय या लीजेंड बनते हैं ।''

सुविचार

यदि आप सभी त्रुटियों के लिए दरवाजा बंद कर दोगे, तो सच्चाई बंद हो जाएगी।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

हेरफेर का अंबार

उच्चतम न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल के स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध ठहराए जाने का फैसला तृणमूल कांग्रेस सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। दर्जनों याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने जो टिप्पणी की, उससे संपूर्ण चयन प्रक्रिया को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। शिक्षा जैसे अत्यंत सम्मानजनक एवं पावन क्षेत्र में इतनी धांधली! जब प्रक्रिया ही त्रुटिपूर्ण थी तो चुने गए शिक्षकों ने कैसी पढ़ाई कराई होगी? उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? न्यायालय का फैसला आते ही उन शिक्षकों के घरों में कैसा माहौल होगा? जो कल तक स्कूलों में सरकारी नौकरी कर रहे थे, आज बेरोजगार हो गए! अब उनका गुजारा कैसे चलेगा? न्यायालय ने तो न्याय किया है, उन नेताओं और अधिकारियों ने क्या किया, जिन पर चयन प्रक्रिया की पवित्रता और विश्वसनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी थी? जब चयन प्रक्रिया में इतनी गलतियां थीं तो उच्चतम न्यायालय में इसके पक्ष में तर्क कितनी देर तक टिकते? इसमें जिस स्तर पर गड़बड़ी हुई, उसका अंदाजा प्रधान न्यायाधीश के इन शब्दों से लगाया जा सकता है, 'हमारे विचार में यह ऐसा मामला है, जिसमें पूरी चयन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है। बड़े पैमाने पर हेरफेर और धोखाधड़ी के साथ-साथ मामले को छिपाने के प्रयासों ने चयन प्रक्रिया को इतना नुकसान पहुंचाया है कि उसे दुरुस्त नहीं किया जा सकता।' इस चयन प्रक्रिया ने समाज को दोहरा नुकसान पहुंचाया है। एक ओर तो इसने उन लोगों का हक मारा, जो सरकारी शिक्षक बनने के योग्य थे। अगर उन्हें नियुक्ति मिलती तो वे शिक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान देते। वहीं, हेरफेर और तमाम त्रुटियों के बावजूद जो लोग अब तक नौकरी करते रहे, उनका भविष्य अनिश्चितता के भंवर में फंस गया है। अमान्य घोषित किए गए हर कर्मचारी पर घर-परिवार के तीन-चार सदस्यों की जिम्मेदारी तो होगी ही। स्पष्ट है कि इस फैसले से एक लाख से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे।

यह गनीमत समझें कि फैसला सुनाते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि 'जिन कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द की गई हैं, उन्हें अब तक अर्जित वेतन और अन्य भत्ते वापस करने की जरूरत नहीं है।' अगर यह राशि वापस लौटानी पड़ती तो इन लोगों के लिए भारी मुसीबत खड़ी हो जाती। हालांकि मुसीबतें अब भी कम नहीं हैं। सरकारी नौकरी लगने के बाद हर महीने बढ़िया वेतन आ रहा था। खास तरह की सामाजिक प्रतिष्ठा थी। अब ये दोनों चीजें जाती रहीं। अगर भविष्य में फिर ऐसी नौकरी हासिल करना चाहेंगे तो संघर्ष कम नहीं है। देश में पहले ही इतनी बेरोजगारी है। सवाल है- क्या इस स्थिति को टाला जा सकता था? जवाब है- बिल्कुल टाला जा सकता था, बशर्ते कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से निभाते। अगर इसमें पारदर्शिता बरती जाती, छेड़छाड़ न होती, अनियमितताओं को दूर रखा जाता तो कोई विवाद ही न होता। उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा के निशाने पर आ गई हैं। विपक्ष उनकी आलोचना करने का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देगा। उसने बनर्जी के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी है। राज्य में विधानसभा चुनाव होने में लगभग एक साल का समय बचा है। भाजपा यह मुद्दा उठाकर तृणकां पर हमला बोल सकती है। चूंकि यह किसी एक ग्राम पंचायत या जिले का नहीं, बल्कि पूरे प. बंगाल के हजारों परिवारों का मुद्दा है, लिहाजा तृणकां के लिए भाजपा के सवालों का जवाब देना आसान नहीं होगा। इस भर्ती घोटाले की जांच की आंच तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं तक पहले ही पहुंच चुकी है। क्या ममता बनर्जी उन सबको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगी या 'जिताऊ' समझकर टिकट देंगी? 'मां, माटी और मानुष' (माता, भूमि और लोग) महज़ नारा बनकर न रह जाए। जिनकी वजह से हजारों 'मानुष' के सपने चकनाचूर हुए, जनता उनका हिसाब जरूर लेगी।

ट्वीटर टॉक

वक्फ विधेयक-2025 का मूल उद्देश्य रिफॉर्म्स लाकर वक्फ की प्रॉपर्टी का उचित मैनेजमेंट करना है। इस सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि पीएम श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करके आगे बढ़ रही है।

-जेपी नड्डा

राजस्थान सरकार में मेरी सहयोगी एवं राज्य मंत्री डॉ. मंजू बाघमार जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम आपको उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ एवं मंगलमय जीवन प्रदान करें, ऐसी शुभकामनाएं हैं।

-भजनलाल शर्मा

ऐसा लगता है कि भारत सरकार महंगाई, बेरोजगारी, शेयर मार्केट में चल रही गिरावट, रुपये के अवमूल्यन जैसे जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बार-बार अल्पसंख्यक वर्ग को निशाने पर लेने वाले कानून बनाती है।

-अशोक गहलोत

प्रेरक प्रसंग

आत्मसम्मान की रक्षा

स्वामी विवेकानंद लाहौर में अपने कुछ अनुयायियों के साथ एक धार्मिक बैठक में भाग लेने गए थे। वहां स्वामी विवेकानंद एक छोटे से बाजार से गुजर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक वृद्ध महिला एक दुकान से बर्तन खरीद रही थी। वह महिला गरीब थी और बाजार में बहुत परेशान दिख रही थी। स्वामी विवेकानंद ने महिला को देखा और बिना किसी भूमिका के उसके पास गए। उन्होंने महिला से पूछा, 'आप इतनी परेशानी में क्या खरीदने की कोशिश कर रही हैं?' महिला ने जवाब दिया, 'बर्तन, जिन्हें घर में इस्तेमाल करना है। यह मेरे परिवार की जरूरत है, लेकिन मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं।' स्वामी विवेकानंद ने महिला को देखा और बिना एक शब्द बोले अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर महिला को दे दिए। महिला चुपचाप पैसे लेकर चली गई। इसके बाद उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि हमारी सभ्यता और हमारी सोच का मूल यही होना चाहिए, ताकि हम किसी भी व्यक्ति को आत्मसम्मान और सम्मान से जीने का अवसर दे सकें।

सामयिक

संघ की राय के बाद अध्यक्ष का नाम तय!

बाल मुकुन्द ओझा

मोबाइल : 8949519406

सियासी पंडितों और जानकारों का मानना है कोई माने या न माने मगर यह आईने की तरह साफ़ है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की नागपुर में संघ प्रमुख और संघ के अन्य पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय हो गया है। अत्यंत विश्वस्त सूत्रों का कहना है संघ अभी से अगले प्रधान मंत्री के लिए अपनी रूपरेखा पर मंथन किया है। जिसकी जानकारी मोदी को दे दी गई है। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी मंथन से निकलने की बात भी कही जा रही है। हालांकि संघ ने भाजपा के अंदरूनी मामलों में किसी हस्तक्षेप से इंकार किया है। संघ प्रवक्ता का कहना है संघ की राय लेने के लिए सभी संगठन स्वतंत्र है, मगर निर्णय उनका खुद का होगा।

भाजपा और संघ के जानकारों का कहना है मोदी के मन की थाह लगाना मुश्किल है। भाजपा में कई फैसले ऐसे लिए गए हैं जो बेहद चौंकाने वाले थे। खट्टर से लेकर भजन लाल तक के नाम इसमें शुमार किये जा सकते है, जिनकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मोदी को ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो उनका विश्वस्त तो हो ही साथ में उसे अगला चुनाव जिताने की भरपूर क्षमता और सम्भावना हो। बिहार और बंगाल सहित अनेक विधान सभाओं के चुनाव नये अध्यक्ष के कार्यकाल में संपन्न होंगे इसीलिए फूंक फूंक कर कदम उठाये जा रहे है। ऐसा माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया संसद सत्र के 4 अप्रैल को समाप्त होते ही तेजी पकड़ने की संभावना है। भाजपा सूत्रों की जानकारी के अनुसार, पार्टी को अप्रैल के तीसरे हफ्ते तक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। पार्टी में 19 प्रदेश अध्यक्षों के नामों की घोषणा के बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। अगले एक हफ्ते में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के नामों का एलान होने की संभावना है। भाजपा के संविधान के मुताबिक, जब तक संगठनात्मक चुनाव आधे से ज्यादा राज्यों में नहीं हो जाते, तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव शुरू नहीं किया जा सकता। फिलहाल, 13 राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे हो चुके हैं और बाकी 19 राज्यों के अध्यक्षों की घोषणा होते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा।

इसी बीच पार्टी विथ डिफरेंस और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा में नये अध्यक्ष को लेकर तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त हो रही हैं। दक्षिण भारत और उत्तर भारत की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। अनेक बड़े और दमदार नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, जो पार्टी के इस महत्वपूर्ण पद के लिए दावेदार हैं। इसी बीच मीडिया में प्रमुखता से एक दर्जन नामों की चर्चा सुनी जा रही है। इनमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, देवेंद्र फडणवीस, मनोहर लाल खट्टर, समृति ईरानी, रघुवर दास सहित जी किशन रेडडी, बंडी संजय कुमार और प्रह्लाद जोशी के नाम प्रमुखता से लिए जा रहे है। किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष का दारोमदार सौंपने की चर्चाएं भी है। संघ के पसंद- नापसंद की चर्चाएं भी छाई हुई है। निवर्तमान अध्यक्ष नड्डा, मोदी और शाह के विश्वसनीय है। खुद का कोई विशेष जनाधार नहीं है। अपने गृह राज्य हिमाचल के विधान सभा चुनाव में वह पार्टी को विजयश्री नहीं दिला पाए। यह भी कहा जा रहा है मोदी और शाह अपने फैसलों से चौंकाते रहे है। राज्यों में मुख्यमंत्री का चयन हो चाहे केंद्र सरकार में मंत्री का चुनाव, सभी मौकों पर चौंकाने वाले फैसले सामने आते रहे हैं। इसलिए यह कहने वालों की कमी नहीं है कि मोदी, पार्टी और देश को एकबार फिर चौंका सकते है।

भाजपा के लिए नया अध्यक्ष बेहद महत्वपूर्ण होगा। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी ने जो रणनीतियां बनाई हैं, उनके साथ नए अध्यक्ष को तालमेल बैठाना होगा। उसे पार्टी के संगठन को नई दिशा देने के साथ-साथ युवाओं को जोड़ने और आगामी चुनावों की तैयारियों में सक्रिय भूमिका के साथ एनडीए के साथी संगठनों से बेहतर समन्वय स्थापित करना होगा। इसलिए पार्टी को एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जुड़ा हो और संगठनात्मक दृष्टि से मजबूत हो। साथ ही मोदी और शाह के भरोसे का हो।

विशेष

पं. माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती प्रसंग पर विशेष

जब पत्रकारिता ने चलाया गो-संरक्षण का सफल आंदोलन

लोकेन्द्र सिंह

मोबाइल : 9893072930

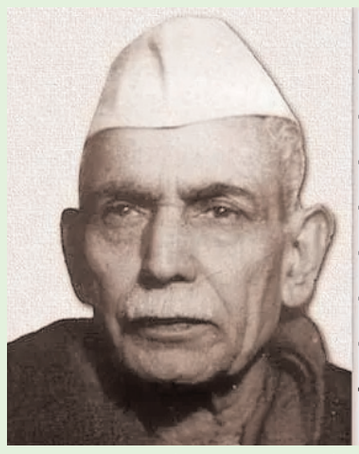

कर्मवीर के माध्यम से गो-संरक्षण के प्रति ऐसी जाग्रती आई कि पहले से संचालित कसाईखाने भी स्वतः बंद हो गए। हिंदू-मुस्लिम सौहार्द्र का वातावरण बना सो अलग। दादा माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रकारिता का यह प्रसंग किसी भव्य मंदिर के शिखर कलश के दर्शन के समान है। यह प्रसंग पत्रकारिता के मूल्यों, सिद्धांतों और प्राथमिकता को रेखांकित करता है। यह 'पत्रकारिता' का सौभाग्य था कि उसे दादा माखनलाल जैसा सुयोग्य संपादक प्राप्त हुआ, जिसने भारत की 'पत्रकारिता में भारतीयता' के भाव की स्थापना की। माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय पत्रकारिता के ऐसे प्रकाश स्तम्भ हैं, जिनसे आज भी भारत की पत्रकारिता आलोकित हो सकती है।

पंडित माखनलाल चतुर्वेदी उन विरले स्वतंत्रता सेनानियों में अग्रणी हैं, जिन्होंने अपनी संपूर्ण प्रतिभा को राष्ट्रीयता के जागरण एवं स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। अपने लंबे पत्रकारीय जीवन के माध्यम से माखनलाल जी ने रचना, संघर्ष और आदर्श का जो पाठ पढ़ाया वह आज भी हतप्रभ कर देने वाला है। आज की पत्रकारिता के समक्ष जैसे ही गो-हत्या का प्रश्न आता है, वह हिंदुत्व और सेकुलरिज्म की बहस में उलझ जाता है। इस बहस में मीडिया का बड़ा हिस्सा गाय के विरुद्ध ही खड़ा दिखाई देता है। सेकुलरिज्म की आधी-अधूरी परिभाषाओं ने उसे इतना भ्रमित कर दिया है कि वह गो-संरक्षण जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय को सांप्रदायिक मुद्दा मान बैठा है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में गो-संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को समझना कोई टेढ़ी खीर नहीं। हद तो तब हो जाती है जब मीडिया गो-संरक्षण या गो-हत्या को हिंदू-मुस्लिम रंग देने लगता है। गो-संरक्षण शुद्धतौर पर भारतीयता का मूल है। इसलिए ही एक भारतीय आत्मा' के नाम से विख्यात महान संपादक पंडित माखनलाल चतुर्वेदी गोकशी के विरोध में अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी पत्रकारिता के माध्यम से देशव्यापी आंदोलन खड़ा कर देते हैं। गोकशी का प्रकरण जब उनके सामने आया, तब उनके मन में द्वंद्व कतई नहीं था। उनकी दृष्टि स्पष्ट थी- भारत के लिए गो-संरक्षण आवश्यक है। कर्मवीर के माध्यम से उन्होंने खुलकर अंग्रेजों के विरुद्ध गो-संरक्षण की लड़ाई लड़ी और अंत में विजय सुनिश्चित की।

वर्ष 1920 में मध्यप्रदेश के शहर सागर के समीप रतौना में ब्रिटिश सरकार ने बहुत बड़ा कसाईखाना खोलने का निर्णय लिया। इस कसाईखाने में केवल गोवंश काटा जाना था। प्रतिमाह ढाई लाख गोवंश का कत्ल करने की योजना थी। अंग्रेजों की इस बड़ी परियोजना का संपूर्ण विवरण देता हुआ चार पृष्ठ का विज्ञापन अंग्रेजी समाचार-पत्र हितवाद में प्रकाशित हुआ। परियोजना का आकार कितना बड़ा था, इसको समझने के लिए इतना ही पर्याप्त होगा कि लगभग 100 वर्ष पूर्व कसाईखाने की लागत लगभग 40 लाख रुपये थी। गो-मांस के परिवहन के लिए कसाईखाने तक रेल लाइन डाली गई थी। तालाब खुदवाये गए थे। कत्लखाने का प्रबंधन सेंट्रल प्रोविंसेज टेनिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी ने अमेरिकी कंपनी सेंट डेविन पोर्ट को सौंप दिया था, जो डिब्बाबंद बीफ को निर्यात करने के लिए ब्रिटिश सरकार की अनुमति भी ले चुकी थी। गोवंश की हत्या के लिए यह कसाईखाना प्रारंभ हो पाता उससे पहले ही दैवीय योग से महान कवि, स्वतंत्रता सेनानी और प्रख्यात संपादक पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने यात्रा के दौरान यह विज्ञापन पढ़ लिया। वह तत्काल अपनी यात्रा खत्म करके वापस जबलपुर लौटे। वहाँ उन्होंने अपने समाचार पत्र कर्मवीर में रतौना कसाईखाने के विरोध में तीखा संपादकीय लिखा और गो-संरक्षण के समर्थन में कसाईखाने के विरुद्ध व्यापक आंदोलन चलाने का आह्वान किया। सुखद तथ्य यह है कि इस कसाईखाने के विरुद्ध जबलपुर के एक और पत्रकार उर्दू दैनिक समाचार पत्र 'ताज' के संपादक मिस्टर ताजुद्दीन मोर्चा पहले ही खोल चुके थे। उधर, सागर में मुस्लिम नौजवान और पत्रकार अब्दुल गनी ने भी पत्रकारिता एवं सामाजिक आंदोलन के माध्यम से गोकशी के लिए खोले जा रहे इस कसाईखाने का विरोध प्रारंभ कर दिया। मिस्टर ताजुद्दीन और अब्दुल गनी की पत्रकारिता में भी गोहत्या पर वह द्वंद्व नहीं था, जो आज की मीडिया में है।

दादा माखनलाल चतुर्वेदी की प्रतिष्ठा संपूर्ण देश में थी। इसलिए कसाईखाने के विरुद्ध माखनलाल चतुर्वेदी की कलम से निकले आंदोलन ने जल्द ही राष्ट्रव्यापी रूप ले लिया। देशभर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में रतौना कसाईखाने के विरोध में लिखा जाने लगा। लाहौर से प्रकाशित लाला लाजपत राय के समाचार पत्र वंदेमातरम ने तो एक के बाद एक अनेक आलेख कसाईखाने के विरोध में प्रकाशित किए। दादा माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रकारिता का प्रभाव था कि मध्यभारत में अंग्रेजों की पहली हार हुई। मात्र तीन माह में ही अंग्रेजों को कसाईखाना खोलने का निर्णय वापस लेना पड़ा। आज उस स्थान पर पशु प्रजनन का कार्य संचालित है। जहाँ कभी गो-रक्त बहना था, आज वहाँ बड़े पैमाने पर दुग्ध उत्पादन हो रहा है।

कर्मवीर के माध्यम से गो-संरक्षण के प्रति ऐसी जाग्रती आई कि पहले से संचालित कसाईखाने भी स्वत: बंद हो गए। हिंदू-मुस्लिम सौहार्द्र का वातावरण बना सो अलग। दादा माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रकारिता का यह प्रसंग किसी भव्य मंदिर के शिखर कलश के दर्शन के समान है। यह प्रसंग पत्रकारिता के मूल्यों, सिद्धांतों और प्राथमिकता को रेखांकित करता है।

यह 'पत्रकारिता' का सौभाग्य था कि उसे दादा माखनलाल जैसा सुयोग्य संपादक प्राप्त हुआ, जिसने भारत की 'पत्रकारिता में भारतीयता' के भाव की स्थापना की। माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय पत्रकारिता के ऐसे प्रकाश स्तम्भ हैं, जिनसे आज भी भारत की पत्रकारिता आलोकित हो सकती है।

नजरिया

नवपद आयंबिल ओली की महिमा और परंपरा

डॉ. दिलीप धींग

मोबाइल : 9952048107

अप्रेल-2021 में कोविड-19 महामारी के चलते पूरे देश में कठोर लॉकडाउन था। उसमें सभी प्रकार के भोजन पैकेट के वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध था। इसके बावजूद बम्बई उच्च न्यायालय ने 16 अप्रेल 2021 को 'आयंबिल आहार पैकेट' को तपस्वियों के घरों तक पहुँचाने की अनुमति दी थी। कहा जा सकता है कि निर्दोष आयंबिल तप और सादे भोजन की महिमा की न्यायालय ने भी अनुमोदना की।

भारतीय पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से वर्ष का शुभारंभ होता है। वर्ष का यह पहला उजला पक्ष आराधना का पखवाड़ा है। इसमें भारत के सभी धर्मों और समुदायों से जुड़े पर्व आते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, युगादि, गुडी पड़वा या चेती चंद से शुरू होकर चैत्री पूर्णिमा हुनमान जयंती तक विभिन्न आराधनाएँ होती हैं। जिनमें चैत्री नवरात्रि, गणगौर, रामनवमी, तीर्थंकर महावीर जन्म कल्याणक आदि प्रमुख हैं। इसी पखवाड़े में जैन धर्मावलम्बी नौ दिवसीय आयम्बिल ओली तप की आराधना करते हैं। यह तपाराधना चैत्र शुक्ल सप्तमी से शुरू होकर पूर्णिमा को पूर्ण होती है। 2025 की चैत्री आयंबिल ओली की शुरूआत 4 अप्रेल, शुक्रवार से हो रही है, जिसका समापन 12 अप्रेल, शनिवार को होगा। 13 अप्रेल, रविवार, बैशाख बदी एकम को तपस्वी पारणा करेंगे।

नवरात्रि की तरह आयंबिल ओली भी वर्ष में दो बार आती है। चैत्री ओली के अलावा दूसरी नवपद ओली आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में आती है। वह भी सप्तमी से शुरू होकर पूर्णिमा को सम्पन्न होती है। आराधक नौ दिनों तक निरन्तर आयम्बिल तप करते हैं। इस विशिष्ट तप के अन्तर्गत दिन में एक बार, एक ही आसन पर परिमित रुक्ष अन्नाहार मात्र किया जाता है। सूरज की साक्षी में यानी दिन के समय में ही उबले या धोवन पानी का सेवन किया जाता है। इस तप में उबले, सिके या प्रासुक अन्नाहार के अलावा दूध, घी, तेल, फल, शाक-भाजी, शक्कर, गुड़, मिर्च, मसाला आदि से युक्त किसी भी प्रकार का भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है।

आयंबिल तन-मन की स्वस्थता, आरोग्य और स्वाद-विजय का तप है। जैन ग्रंथों में 12 प्रकार के तपों में इसे रस-परित्याग तप के अंतर्गत परिगणित किया गया है। इसे महात्मा गांधी ने अस्वाद-व्रत कहा था तथा अपने आश्रम के व्रत विधान में इसे मामूली परिवर्तन के साथ सम्मिलित किया था। इस आराधना में नौ दिनों तक क्रमशः अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के पदों की जप-साधना की जाती है। कुछ साधक इस आराधना में निर्दिष्ट रंग के अन्न का सेवन और निर्दिष्ट रंग की माला से जप-ध्यान करते हैं। इस साधना के लिए सिद्धचक्र का आलंबन भी लिया जाता है।

आयंबिल ओली के नौ दिनों तक श्रीपाल और मैनासुंदरी की कथा के वाचन और श्रवण की परंपरा है। प्राचीन जैन ग्रंथों में प्राप्त इस कथा के अनुसार मैनासुंदरी का विवाह कुष्ठरोगी श्रीपाल से हो जाता है। श्रीपाल के पाँच सौ साथी भी कोढ़ी थे। उस विकट स्थिति में भी मैनासुंदरी अपने पति या किसी भी रोगी से बिलकुल घृणा नहीं करती है। वह अपने पति के साथ अचल श्रद्धा और भक्तिपूर्वक आयंबिल तप और नवपद की आराधना करती है। जप-तप के प्रभाव से नौ दिनों में श्रीपाल का कुष्ठरोग नष्ट हो जाता है। उनकी जप-तप की साधना से अभिमंत्रित जल के छिड़काव से शेष 500 कोढ़ियों का कोढ़ भी खत्म हो जाता है।

स्वस्थ होने के बाद श्रीपाल राजा बन जाते हैं और नियमानुसार मैनासुन्दरी रानी। इस तरह मैनासुन्दरी ने आयंबिल तप और नवपद के जप से अपने दुर्भाग्य को सुख-सौभाग्य में बदल दिया। आज भी जैन समाज के लोकजीवन में आयंबिल तप को विघ्न-निवारक, आरोग्य-प्रदायक और सौभाग्य-वर्धक माना जाता है। आयंबिल तप और नवपद जप के अनेक चमत्कार जनजीवन में प्रसिद्ध हैं। इसी कथा के अनुसार जैन परम्परा में नौ दिवसीय नवपद आयंबिल ओली की व्यक्तिगत और सामूहिक आराधना की जाती है। इस तप आराधना में आराधक केवल उबले अन्न का सेवन करते हैं। जैन समाज में यह तप इतना प्रसिद्ध है कि स्थान-स्थान पर बारहमासी आयंबिल शालाएँ चलती हैं। नवपद आयंबिल ओली के नौ दिनों में समाज की संस्थाओं और मंदिरों द्वारा इस तप के लिए सादे अन्नाहार का विशेष प्रबंध किया जाता है, जिससे आराधक निश्चिन्त होकर आराधना कर सके।

अप्रेल-2021 में कोविड-19 महामारी के चलते पूरे देश में कठोर लॉकडाउन था। उसमें सभी प्रकार के भोजन पैकेट के वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध था। इसके बावजूद बम्बई उच्च न्यायालय ने 16 अप्रेल 2021 को 'आयंबिल आहार पैकेट' को तपस्वियों के घरों तक पहुँचाने की अनुमति दी थी। कहा जा सकता है कि निर्दोष आयंबिल तप और सादे भोजन की महिमा की न्यायालय ने भी अनुमोदना की।

महत्त्वपूर्ण

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**Regn No.RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।- **दक्षिण भारत राष्ट्रमत**

अमेरिका का शुल्क में वृद्धि का दांव 'उल्टा पड़ेगा', भारत पर प्रभाव कम: रघुराम राजन

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बृहस्पतिवार को कहा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का लगभग 60 देशों पर लगाया गया जवाबी शुल्क का दांव 'उल्टा पड़ेगा' और भारत पर इसका प्रभाव 'कम' होगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सभी व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 10 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त मूल्य-आधारित शुल्क लगाने की घोषणा की है। उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, ''हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि अल्पावधि में, इसका सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह 'सेल्फ गोल' (खुद को नुकसान पहुंचाने) है। अन्य देशों पर पड़ने वाले प्रभावों की बात करें तो भारत के निर्यात पर किसी भी शुल्क का सीधा प्रभाव यह होगा कि अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ेंगी, इससे उनकी मांग कम होगी और फलस्वरूप भारत की आर्थिक वृद्धि प्रभावित होगी।''

दस प्रतिशत का मूल शुल्क पांच अप्रैल से और 27 प्रतिशत नौ अप्रैल से प्रभावी होगा। कुछ क्षेत्रों को शुल्क से छूट दी गई है। इनमें औषधि, सेमीकंडक्टर और ऊर्जा उत्पाद शामिल हैं।

जाने-माने अर्थशास्त्री ने कहा, ''वास्तव में, चूंकि अमेरिका ने अन्य देशों पर भी शुल्क लगाया है तथा भारत उन देशों के उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है, ऐसे में कुल मिलाकर इसका प्रभाव केवल भारत पर शुल्क लगाने के मुकाबले कम होगा क्योंकि अमेरिकी उपभोक्ता विकल्प के तौर पर गैर-शुल्क उत्पादकों के पास तो जा पाएंगे नहीं।''

वर्तमान में बिजनेस स्कूल, शिकॉगो बूथ में प्रोफेसर, राजन ने कहा कि ट्रंप का दीर्घकालिक मकसद अमेरिकी उत्पादन को बढ़ाना है, लेकिन, यदि यह संभव भी हो, तो इसे हासिल करने में लंबा समय लगेगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत पर अमेरिका के जवाबी शुल्क संभवतः महंगाई बढ़ाने वाला नहीं होगा, क्योंकि भारत कम निर्यात करेगा और घरेलू स्तर पर आपूर्ति अधिक होगी। चीन जैसे अन्य देश अब भारत को निर्यात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अमेरिकी बाजार अधिक बंद है।

यह पूछे जाने पर कि क्या भारत इस संकट को अवसर में बदल सकता है, राजन ने कहा, ''हम निश्चित रूप से उन शुल्क को कम कर सकते हैं जिन्हें हम बढ़ा रहे हैं। यह भारत के लिए फायदेमंद होगा, भले ही इससे हमें अमेरिकी शुल्क को कम करने में मदद मिले या नहीं।'' उन्होंने कहा कि भारत को यह समझने की आवश्यकता है कि दुनिया बहुत अधिक संरक्षणवादी हो गई है, इसलिए हमें व्यापार को लेकर अधिक चतुराई से काम करना होगा।

राजन ने उदाहरण देते हुए कहा कि पूर्व में आसियान और जापान, दक्षिण पश्चिम में अफ्रीका और उत्तर पश्चिम में यूरोप की ओर देखने का मतलब बनता है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ बराबरी का संबंध स्थापित करना प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही, हमें अपने पड़ोसी देशों, दक्षेस (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) के साथ भी मजबूत संबंध बनाने चाहिए।''

अभिनेता वीर दास ने 'द आउटसाइडर' के जरिये लेखन में पदार्पण किया

मुंबई/भाषा। स्टैंड-अप कॉमेडियन और अभिनेता वीर दास ने कहा कि उन्होंने द आउटसाइडर नामक संस्मरण के तौर पर अपनी पहली किताब लिखी है।

'इंटरनेशनल एमी' विजेता हास्य अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर यह खबर साझा की। उन्होंने सोशल मीडिया मंच पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उनके जीवन व करियर के विभिन्न अध्यायों को प्रदर्शित किया गया है। दास ने कहा, मैंने एक किताब लिखी है। सभी ' द आउटसाइडर्स' (बाहरी लोगों) के लिए। दास ने कहा कि कुछ कारणों से, उन्होंने दुनिया को अधिक देखा है, और उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को दूसरों की तुलना में अधिक जानने का मौका मिला है। उन्होंने कहा, हास्य ने वाकई मेरी जान बचाई है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यह दुनिया कितनी मज़ेदार और खूबसूरत है। यह (किताब) जल्द ही दुकानों पर उपलब्ध होगी, लेकिन आप अभी इसे मेरी प्रोफाइल में जाकर ऑर्डर कर सकते हैं।

एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह किताब अमेरिका में 'साइमन एंड शूस्टर' और भारत में 'हार्पर कॉलिन्स' द्वारा प्रकाशित की जाएगी।

भारत में जन्मे दास ने अपने प्रारंभिक वर्ष भारत और नाइजीरिया के लागोस में बिताए और अक्सर वह बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस करते थे।

पोज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बैंकॉक थाईलैंड में रामायण के थाई रूपांतरण, रामकियेन का प्रदर्शन करने वाले कलाकारों के साथ पोज देते हुए।

म्यांमार भूकंप : मांडले में भारतीय टीम बचाव कार्य के साथ स्थानीय लोगों का दिल भी जीत रही

मांडले (म्यांमार)/भाषा। म्यांमार में गत शुक्रवार को 7.7 तीव्रता का भूकंप आने और उसके बाद मदद को पहुंची भारतीय टीम विपरीत परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्य को अंजाम तो दे ही रही है; साथ ही स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान कर उनका दिल भी जीत रही है। इसी का उदाहरण मांडले में मलबे से एक शव को निकालते समय देखने को मिला।

मलबे में फंसे शव को देखकर प्रतीत होता था कि महिला और उसका बच्चा उस समय भूकंप की चपेट में आ गए जब वे नमाज़ पढ़ रहे थे। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के कर्मियों ने पूर्व शाही राजधानी मांडले में स्ट्रीट 86ए के पास इस आपदा स्थल पर स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए शव निकालने से कदम पीछे खींच लिए।

एनडीआरएफ के एक सदस्य ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, ''लेकिन समय गुजरने के साथ ही शव सड़ने लगा था। परिजनों को एहसास हुआ कि शव को पूरी तरह से निकालने के लिए उनके पास विशेषज्ञता का अभाव है, इसलिए वे हिचकिचाने लगे। उनकी शुरुआती अनिच्छा बाद में अपील में बदल गई।'' उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ कर्मियों ने अपना कार्य पुनः शुरू किया, महिला के शव को सावधानीपूर्वक बाहर निकाला तथा नमाज़ की उसकी अंतिम मुद्रा की गरिमा को बनाए रखा।

मौके पर मौजूद एनडीआरएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, ''जो लोग मदद स्वीकार करने में झिझक रहे थे, अब वे आभार जताते थक नहीं रहे हैं।''

म्यांमार में एनडीआरएफ खोज एवं बचाव अभियान दल के उप टीम लीडर डिप्टी कमांडर कुणाल तिवारी ने बताया कि टीम को शव प्रबंधन में प्रशिक्षित किया गया है।

आदम हुसैन (65) ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि भूकंप उस समय आया जब मुस्लिम पवित्र महीने रमजान के अंतिम जुमे (शुक्रवार) पर अलविदा की नमाज अदा कर रहे थे।

राहत और बचाव कार्यों के लिए मांडले शहर को चार सेक्टरों- अल्फा, ब्रावो, चार्ली और डेल्टा में बांटा गया है।

'पंचायत 4' की रिलीज डेट आई सामने, लौट रही फुलेरा गांव की मंडली

मुंबई/एजेन्सी

लोकप्रिय वेब सीरीज 'पंचायत' ने रिलीज के 5 साल पूरे कर लिए हैं। इसी बीच प्राइम वीडियो ने कॉमेडी-ड्रामा के बहुप्रतीक्षित सीजन 4 की घोषणा की है। एक बार फिर से फुलेरा गांव के सचिव जी अपनी मंडली के साथ दर्शकों को एंटरटेनमेंट का फुल डोज देने के लिए तैयार हैं।

साल 2020 में ग्रामीण जीवन पर बनी सीरीज 'पंचायत' का सफर शुरू हुआ था। अपने तीन शानदार पड़ाव पूरे कर चुका सीरीज का सीजन 4 ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर 2 जुलाई को प्रीमियर के लिए तैयार है, जिसमें पसंदीदा किरदारों और उनके जीवन की कहानी का मजेदार सफर देखने को मिलेगा। सामने आए लेटेस्ट सीजन के वीडियो में सचिव जी, प्रधान जी और फुलेरावासियों को नई चुनौतियों का सामना करते और कुछ अनोखे कारनामों को अंजाम देते दिखाया जाएगा।

'पंचायत' में जितेंद्र कुमार 'सचिव जी' की भूमिका में हैं, साथ ही रघुबीर यादव, नीना गुप्ता, संविका, चंदन रॉय, फैसल मलिक, दुर्गेश कुमार, सुनीता राजवर और पंकज झा जैसे बेहतरीन कलाकारों ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं। 'पंचायत' ग्रामीण भारत की पृष्ठभूमि पर आधारित दिल को छू लेने वाली कॉमेडी और मनोरंजन से भरपूर सीरीज है। यह शो अभिषेक (जितेंद्र कुमार) के जीवन पर आधारित है, जिसे फुलेरा गांव में ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है। गांव के जीवन से नाखुश अभिषेक पंचायत कार्यालय में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर देता है। अपनी यात्रा के दौरान अभिषेक प्रधान-पति (रघुबीर यादव), गांव की प्रधान (नीना गुप्ता), प्रह्लाद चा (फैसल मलिक) और ग्राम पंचायत के कार्यालय सहायक विकास (चंदन रॉय) का खास दोस्त बन जाता है। द वायरल फीवर ने 'पंचायत' को दीपक कुमार मिश्रा और चंदन कुमार के साथ मिलकर बनाया है। चंदन कुमार ने सीरीज की पटकथा भी तैयार की है और निर्देशन का भार दीपक कुमार मिश्रा और अक्षत विजयवर्गीय ने संभाला है। ग्रामीण भारतीय पृष्ठभूमि पर बनी यह सीरीज शहरों और गांव की जिंदगी के बीच लोगों के हर दिन की चुनौतियों और राजनीतिक दांव-पेंच में उलझी कहानियों को दिखाती है। जिसमें आपके लिए संदेश भी है और यह भी बताने की कोशिश है कि आगे बढ़ते जाने का नाम ही जिंदगी है।

प्राइम वीडियो ने रिलीज किया 'छोरी-2' का ट्रेलर

मुंबई/एजेन्सी

प्राइम वीडियो ने हॉरर फिल्म छोरी के बहुप्रतीक्षित सीक्वल छोरी 2 का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज कर दिया है। टी-सीरीज़, एबंडेंशिया एंटरटेनमेंट, साइक और टैमारिस्क लेन प्रोडक्शन की हॉरर फिल्म छोरी 2 का निर्देशन विशाल फुरिया ने किया है और इसमें नुसरत भरुचा ने साक्षी के क़िरदार में वापसी की है, उनके साथ सोहा अली ख़ान ने बहुत अहम भूमिका निभाई है, गश्मीर महाजनी, सौरभ गोयल, पल्लवी अजय, कुलदीप सरीन, और हार्दिका शर्मा जैसे कलाकारों भी नज़र आने वाले हैं। भारत और दुनिया भर के 240 से अधिक देशों एवं क्षेत्रों में 11 अप्रैल 2025 को प्राइम वीडियो पर छोरी 2 का एक्सक्लूसिव प्रीमियर होगा।

साक्षी की दुनिया में लौटने के बारे में बताते हुए, नुसरत भरूचा ने कहा, छोरी 2 में साक्षी के रूप में वापसी करना मेरे करियर के सबसे बढ़िया और फ़ायदेमंद तजुर्बों में से एक रहा है। हार माने बिना अपने बच्चे की जान बचाने के सात साल बाद, साक्षी का सबसे गहरा डर

सच्चाई में बदल जाता है, जो कहानी में नए जज़्बात और गहराई में ले जाता है। इस भाग में डर और भी ज़्यादा गहरा, ज़्यादा ताक़तवर और बहुत हद तक असली लगता है क्योंकि ये एक माँ के अत्यंत बुरे सपनों को बयाँ करता है। विशाल ने बड़ी ख़ूबसूरती से सिहरन पैदा कर देने वाले पलों को बेबाक जज़्बातों के साथ तैयार किया है, जिससे कहानी ज़िंदा रहने की भावना, प्यार और एक माँ अपने बच्चे की हिफाज़त करने के लिए किस हद तक जा सकती है, उसका एक मज़ेदार ताना-बाना बन गई है।

छोरी के इस भाग में शामिल होने वाली सोहा अली खान ने कहा, छोरी 2 के हुनरमंद कलाकारों में शामिल होना और इस तरह के दिलकश क़िरदार को निभाना मेरे लिए एक रोमांचक नई चुनौती थी। जिस बात ने मुझे फिल्म की ओर खींचा, वह यह थी कि कैसे यह उथल-पुथल, माहौल के डर को लोक कहानियों को एक साथ मिलाती है जिसकी जड़ें हमारी संस्कृति में है। मेरा किरदार अनेक रंगों वाला है ।इसमें खतरा है लेकिन रहस्य भी है।

वो कोई ऐसी इंसान नहीं है जिसकी आगे की ज़िंदगी को आप आसानी से समझ सकते हैं, जिसने उसे पर्दे पर उतारे जाने के लिए एक मनमोहक क़िरदार बना दिया। विशाल ने एक ऐसी दुनिया तैयार की है जहां हर तरफ से डर चला आता है, और इसका हिस्सा बनने से मुझे एक अदकारा के रूप में खुद के एक बिल्कुल नए पहलू को तलाशने का मौका मिला।

इस फिल्म के बारे में जानकारी देते हुए निर्देशक, विशाल फुरिया ने कहा, छोरी 2 के साथ, हम केवल एक सीक्वल नहीं बनाना चाहते थे। हम हर उस चीज़ को बड़ा करना चाहते थे जिसने पहली फिल्म को इतना ख़ौफ़नाक और भावनात्मक तौर पर ज़बरदस्त बनाया था। इस चैप्टर में छोरी की दुनिया और भी बड़ी हो जाती है; लोक कहानियाँ गहरी हो जाती हैं, और साक्षी का सामना करने वाली शैतानी ताक़त और भी ज़्यादा निजी और ख़तरनाक लगती है। हमने नए किरदार, नए भाग और अनजाने मोड़ पेश किए हैं और वो भी उस असली कहानी को साथ लेकर चलते हुए किया गया है जो कहानी को इसकी ख़ास वास्तविकता प्रदान करती है। इसका सार के रूप में, छोरी 2 एक मां की किसी ऐसी चीज़ के खिलाफ़ लगातार की जाने वाली लड़ाई है जो हर जगह मौजूद है, और यहीं असली दहशत छिपी हुई है।

करीना कपूर खान, आदित्य रॉय कपूर, रोहित सराफ और अन्य सितारें भारत में विविएन वेस्टवुड के डेब्यू शो में हुए शामिल

मुंबई/एजेन्सी

फैशन इंडस्ट्री के सबसे प्रतिष्ठित लग्ज़री ब्रांड्स में से एक, यूके स्थित विविएन वेस्टवुड ने 1 अप्रैल को भारत में अपना पहला शो आयोजित किया। मुंबई के प्रतिष्ठित गेटवे ऑफ इंडिया में हुए इस भव्य आयोजन में पूरा बॉलीवुड सितारों से जगमगा उठा। करीना कपूर खान, मीरा राजपूत, रोहित सराफ, दिशा पटानी, राधिका मर्चेंट, अंजलि मर्चेंट, आदित्य रॉय कपूर, विजय वर्मा, मानुषी छिल्लर, जान्हवी कपूर, ट्विंकल खन्ना, पत्रलेखा, वाणी कपूर सहित कई बड़े सितारों ने इस हाई-प्रोफाइल फैशन इवेंट में शिरकत की। अधिकतर सेलिब्रिटीज ने दिवंगत डिज़ाइनर को श्रद्धांजलि देने के लिए विविएन वेस्टवुड के क्रिएशन्स पहने थे। मुंबई में हुए इस फैशन शो का उद्देश्य भारत की समृद्ध पारंपरिक टेक्सटाइल विरासत को सम्मानित करना और प्रदर्शित करना था। इस आयोजन में विविएन वेस्टवुड के स्प्रिंग-समर 2025 कस्टम लुक्स और आर्काइव पीस पेश किए गए। इसके अलावा, एक विशेष कैप्सूल कलेक्शन भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें हाथ से बुने चंदेरी सिल्क और खादी कॉटन, ऊन व सिल्क से तैयार विविएन वेस्टवुड के हाई-कॉउचर लुक्स शामिल थे। खादी, जिसे महात्मा गांधी ने पुनर्जीवित किया था, भारत में स्वतंत्रता का प्रतीक मानी जाती है।

हाल के वर्षों में, भारत धीरे-धीरे ग्लोबल फैशन इंडस्ट्री में अपनी जगह मजबूत कर रहा है। अबू जानी-संदीप खोसला, गौरव गुप्ता, फाल्गुनी-शेन पीकॉक, राहुल मिश्रा, मनीष मल्होत्रा जैसे भारतीय डिज़ाइनर न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड के बड़े सितारों को भी अपने डिज़ाइन्स में स्टाइल कर रहे हैं।

वहीं, मौनी रॉय जैसी भारतीय हस्तियां भी दुनिया भर के फैशन वीक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ऐसे में, भारत और इंटरनेशनल फैशन इंडस्ट्री के बीच की दूरियां एक-एक फैशन शो के साथ कम होती जा रही हैं!

म्यूनिख की सड़क पर अनुपम खेर ने गाया गाना

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेता अनुपम खेर विदेशों में छुट्टियां मना रहे हैं। इस बीच उन्होंने जर्मनी के म्यूनिख से एक मजेदार पल साझा किया, जहां वह एक स्ट्रीट परफॉर्मर के सामने सड़क पर गाना गाते दिखाई दिए। अभिनेता ने मजेदार मुलाकात से जुड़ा किस्सा भी सुनाया। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने किस्से के बारे में विस्तार से बताया। लिखा, म्यूनिख में एक मजेदार मुलाकात।

मैंने जर्मनी के म्यूनिख में एक स्ट्रीट परफॉर्मर थॉमस स्कॉल से अनुरोध किया कि क्या मैं गा सकता हूं? उसे लगा कि मैं कोई मशहूर गायक हूं, इसलिए उसने मुझे गाने दिया। वह मेरे गाने की भाषा समझने की कोशिश कर रहा था, और जब मेरे खराब गायन की आवाज उसके कान में गई, तो उसे लगा कि यह इतनी खराब आवाज है। खेर ने आगे बताया, उसी समय एक भारतीय साथी मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए आया। यह देखकर उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं कोई मशहूर गायक हूं? इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, वह जोर से हंस पड़ा और जर्मन में कुछ बुदबुदाया! मुझे यकीन है कि उसने कहा होगा, 'उस तरह के गायन से उसके प्रशंसक कैसे हो सकते हैं!'

अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी चैप्टर 2' का ट्रेलर रिलीज

नयी दिल्ली/एजेन्सी

बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म 'केसरी चैप्टर 2' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे के साथ अपनी इस बहुप्रतीक्षित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। इस मौके पर इस फिल्म का नया पोस्टर भी जारी किया गया। फिल्म 'केसरी चैप्टर 2' वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सी. शंकरन नायर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे की सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी थी। ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम में 'केसरी चैप्टर 2' के निर्माता करण जौहर, अपूर्व मेहता, अमृतपाल बिंद्रा के साथ फिल्म के निर्देशक करण सिंह त्यागी भी मौजूद थे। ट्रेलर की शुरुआत 13 अप्रैल, 1919 को जलियांवाला बाग में हुई गोलीबारी की एक झलक के साथ होती है। इसके बाद फिल्म में सीएस नायर की भूमिका निभा रहे अक्षय कुमार नजर आते हैं। वह अदालत में जनरल डायर से सवाल-जवाब करते दिखते हैं। अदालत में वह सवाल करते हैं जनरल डायर आपने जलियांवाला बाग से भीड़ को हटाने के लिए वार्निंग कैसे दी। क्या आपने टियर गैस फेंकी वहां या हवा में गोली चलाई। इस पर जनरल डायर कहते हैं नहीं। इस पर सी एस नायर कहते हैं तो आपने बिना वॉर्निंग दिए भीड़ पर गोली चला दी ये सुनकर जनरल डायर कहते हैं कि वो भीड़ नहीं टेरेरिस्ट थे।इसके बाद आर माधवन को अपोजिशन वकील के रूप में दिखाया गया है।अनन्या पांडे को उन शुरुआती महिलाओं में से एक के रूप में भी दिखाया गया है जिन्होंने उस समय कानून की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया था जब इसे सिर्फ पुरुषों का काम माना जाता था।

फिल्म का नया पोस्टर जारी करते हुए अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर लिखा, '1650 गोलियां, 10 मिनट और एक आदमी, जो इसके खिलाफ दहाड़ता है। भारत को हिला देने वाले भयानक नरसंहार के पीछे की सच्चाई को देखें।' धर्मा प्रोडक्शंस, लियो मीडिया कलेक्टिव और केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा निर्मित, केसरी चैप्टर 2,18 अप्रैल, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
www.dakshinbharat.com
epaper.dakshinbharat.com
चेन्नई | शुक्रवार | 04-04-2025 /dakshinbharat /dakshinbharat DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT HINDI DAILY
RNI No. : TNHIN/2013/52520
Regn No. : TN/CCN/613/2014-2016
posted at Patrika Channel,
Egmore RMS, Chennai-8

जाति, भाषा, प्रांत और संप्रदायों का भेदभाव इतना जहरीला होता है कि वह न्याय, नीति, मानवता और कर्तव्य का बोध कभी नहीं होने देता। इनके बलबूते पर अयोग्य भी सत्ता की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। नीति शास्त्र कहता है कि अयोग्य के पास आई हुई सत्ता, सामर्थ्य और शक्ति सदैव लोगों के शोषण तथा उत्पीड़न का ही काम करती है। कमोबेश हम अपने देश के अनेक प्रांतों में और विश्व के अनेक देशों में यही स्थिति देख रहे हैं। यह कलयुग की करुण दर्दनाक कथा है।

समाज का विकास उसकी संख्या से नहीं, उसकी सही नीति-रीतियों से होता है : आचार्य विमलसागरसूरी

वीवीपुरम में जैनाचार्यों का हुआ आध्यात्मिक मिलन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के वीवीपुरम स्थित संभवनाथ जैन मंदिर के प्रांगण में गुरुवार को जैन समाज के विविध वर्गों की सभा को संबोधित करते हुए आचार्य विमलसागर सूरीश्वरजी ने कहा कि किसी भी समाज का विकास उसकी संख्या, बुद्धिमत्ता अथवा समृद्धि से नहीं, उसकी सही नीति-रीति से होता है। गलत नीतियां समाज के भविष्य को अंधकारमय बना देती हैं। समाज में छोटे-बड़े, सामान्य-विशेष, सभी वर्गों के लोग होते हैं। सबकी बुद्धि, क्षमता, संपत्ति और सामर्थ्य एक जैसे नहीं होते। ऐसे में सबके हितों का चिंतन करके ही समाज को अखंडित, स्वच्छ, प्रगतिशील और मज़बूत रखा जा सकता है। ऊंच-नीच का भेदभाव और धन का बोलबाला समाज के अस्वस्थ होने के संकेत हैं। समाज की अच्छी और बहुहितकारी नीति-रीति ही उसकी परिपक्वता का निर्धारण करती है, इसलिए यह आवश्यक है कि समाज प्रभुत्वशाली श्रीमंतों की मनमानी से नहीं, ज्ञानियों और गुणवान लोगों के आधार पर गति करे। समाज राजनीतिक उठापटक का अखाड़ा न बने। समाज के दीर्घकालीन समुचित विकास के लिए लोगों का जागरूक और सामाजिक संगठनों का मजबूत होना भी अत्यंत जरूरी है। जिसका सांगठनिक ढांचा कमजोर होता है और जिस समाज का प्रबुद्ध वर्ग उदासीन होता है, वह समाज आपसी विवादों और मनमानियों में तबाह हो जाता है।

जैनाचार्य विमलसागर सूरीश्वरजी ने कहा कि दान की घोषणा कर धनराशि तत्काल जमा करवाई जानी चाहिए। दान देने के बाद भी धनराशि पर अपना अधिकार रखना अथवा उसे जमा न करवाना निकृष्ट पाप प्रवृत्ति है। धर्मस्थानों के संचालन भी योग्य लोगों के हाथों में होने चाहिए। आज संस्थाओं में अयोग्य और नासमझ लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। सामाजिक-धार्मिक स्थानों पर धर्म के नीति-नियमों के विरुद्ध आचरण होने लगे हैं। ज्ञानी साधु-संतों के मार्गदर्शन में ही धर्म और समाज की व्यवस्थाओं का संचालन किया जा सकता है। जो लोग सामाजिक-धार्मिक स्थानों पर रात्रिभोजन, अभक्ष्य-जमीकंद आदि का सेवन, शराब, जुआ, किराए के डांसर तथा अन्य अनुचित प्रवृत्तियों को समर्थन देते हैं, वे अपने समाज व धर्म को बिलकुल सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। किसी भी कीमत पर समाज की शादियों में भी शराब, धूम्रपान, हुक्का, जुआ आदि को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए।

ऐसे कुकृत्यों के हिमायती लोगों को हाशिये पर धकेल कर ही हम समाज को स्वच्छ और सुरक्षित रख सकते हैं। जो लोग चार और पांच सितारा होटलों में अपने कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं, वे समाज की गौरवशाली उज्ज्वल परंपराओं को धूमिल कर उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। आज नहीं तो कल, वैभव प्रदर्शन की यह मानसिकता उन्हें और समाज को भारी नुकसान पहुंचाएंगी। आचार्य विमलसागरसूरीश्वर ने आगे कहा कि अंतरजातीय विवाहों को मिलती सामाजिक स्वीकृति भी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

एक तरफ जहां समाज में कन्याओं की संख्या कम हैं और पर्याप्त उम्र होने के बाद भी युवकों को कन्याएं नहीं मिल रही हैं, ऐसी विकट स्थिति में अंतरजातीय विवाहों को मिल रही स्वीकृति भारी सामाजिक असंतुलन पैदा करेगी। इससे समाज में पाखंड बढ़ेगा और समाज रुग्ण बन जाएगा। वर्तमान में यह समस्या समाज की बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कन्याओं के लिए गांवों और कस्बों से लोग निरंतर पलायन कर रहे हैं। दक्षिण भारत में पिछले दस वर्षों में बीस हजार से अधिक परिवार महानगरों के लिए विदा हुए हैं। इससे गांवों और कस्बों की धार्मिक-सामाजिक संस्थाओं तथा उनकी संपत्तियों पर विपत्तियों के बादल मंडराने लगे हैं। निकट भविष्य में समाज संस्थाओं और उसकी संपत्तियों की बदहाली देखेगा।

इससे पूर्व प्रातः बीबीयूएल जैन विद्यालय से आचार्य अभयशेखरसूरीश्वरजी, आचार्य विमलसागरसूरीश्वरजी, गणि पद्मविमलसागरजी आदि साधु-साध्वीगण का गाजेबाजे के साथ स्वागत किया गया। जगह-जगह श्रद्धालुओं ने स्वस्तिक रचना कर संतों को बधाया। महिलाओं ने मंगल कलशों से स्वागत किया। फिर संभवनाथ जिनालय में चतुर्विध संघ ने सामूहिक चैत्यवंदना की। आचार्य अभयशेखरसूरीश्वरजी ने भी धर्मसभा को संबोधित किया।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

सम्मान

सीआईएसएफ बेंगलूरु मुख्यालय के आईजीपी व राजस्थान कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जोस मोहन से बेंगलूरु के प्रवासी राजस्थानी कर्नाटक संघ के महामंत्री जवरीलाल लुनावत व राजेश गुलेच्छा ने उनके यलहंका स्थित कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की तथा उनका सम्मान किया। ज्ञातव्य है कि जोस मोहन के पास लगभग 35 एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था का ज़िम्मा है।

एक शाम मां दधिमति के नाम आज

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। यहां साहुकारपेट के मां दधिमति सेवा धाम में चैत्र नवरात्रि का उत्सव धूमधाम से चल रहा है। प्रतिदिन सुबह मां का दुग्धाभिषेक, अर्चना, श्रृंगार आरती, संध्या एवं शयन आरती आदि का आयोजन हो रहा है। नवरात्रि में सप्तमी के मौके पर विशेष भजन संध्या मा आयोजन 4 अप्रैल को किया जा रहा है। राजस्थान के भजन कलाकार चिंटू दाधीच, जोधपुर अपनी मधुर वाणी से भजनों की प्रस्तुति कर माता रानी के चरणों में भेंट करेंगे। अष्टमी के दिन श्री दधिमती महिला मंडल द्वारा मां दधिमती का मंगल पाठ होगा। इस महोत्सव में समाज के सदस्यों के साथ अनेक भक्तगण शामिल हो रहे हैं।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

गीता सार पर 18 दोहे

1.
उत्तम सोच विचार से, मिट जाता है क्लेश।
जीवन में अपनाइए, गीता का संदेश ।।

2.
सार्थक शिक्षा से सदा, मिलता है निष्कर्ष।
उसके अंदर ही छिपा, होता है उत्कर्ष ।।

3.
कर्म किए जा बेधड़क, फल पर मत दे ध्यान।
जिसके हम हकदार हैं, वो देंगे भगवान ।।

4.
करना हर इक काम को, सच्चे मन के साथ।
जो आ जाए सामने, लेना हाथों हाथ ।।

5.
दंभ कभी मत पालिए, होती है मति मंद।
रहता है मनुहार में, अनुबंधित आनंद ।।

6.
ऊँचे लक्ष्य बनाइए, छोडें निम्न विचार।
होता है संघर्ष से, हर सपना साकार ।।

7.
जो सीखें उसको जिएँ, साथ लिए विश्वास।
हल होता है हर सबक, करने से अभ्यास ।।

8.
जो करते हैं उम्रभर, अपने पर विश्वास।
उनका जीवन में नहीं, होता है उपहास ।।

9.
अपने मतलब के लिए, जो न करे फरियाद।
देना उसको चाहिए, अपना आशीर्वाद ।।

10.
भवसागर में दिव्यता, अंकित है चँहुओर ।
हार कभी मत मानिए, रात रहे या भोर ।।

11.
सच को लें सच की तरह, मानें सच को सत्य ।
आलोकित हो हर जगह, दें न उसे नैपथ्य।।

12.
ईश्वर में हरदम रखें, अपने मन को लीन।
वो ही पालनहार है, उस पर रखें यकीन ।।

13.
पा जाएंगे दिव्यता, ग़र छोड़ेंगे मोह ।
ये जो माया मोह है, देंगे सिर्फ़ बिछोह ।।

14.
जीवन शैली वो जिएँ, खाए खुद से मेल ।
वरना वो संसार में, बन जाएगी खेल ।।

15.
लौकिकता को छोड़कर, जानें दिव्य प्रकाश।
हो जाएगा सामने, नतमस्तक आकाश।।

16.
नेकी का अच्छा सदा, बनता है प्रतिमान।
अच्छा होना लोक में, समझो है वरदान।।

17.
सच में ताकत है बहुत, रहिए सच के साथ।
संकट में भी सत्य का, थामे रखिए हाथ।।

18.
मन में ईश्वर को रखें, छोड़ें कटुता द्वेष।
राह सहज अपनाइए, दिल में रखिए श्लेष ।।

■ माणिक विश्वकर्मा 'नवरंग'
मो.9424141875

अलसूर महिला सदस्याओं ने मंदिर व संतों के किए दर्शन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। स्थानीय श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, अलसूर के तत्वावधान में, महिला मंडल ने महिला दिवस के संदर्भ में तीर्थ दर्शन यात्रा का आयोजन किया। अध्यक्ष आशाबाई बोहरा के नेतृत्व में महिला सदस्याओं ने होसकोटे स्थित नवनिर्मित जीरावला मंदिर में दर्शन कर स्थानक भवन में विराजमान साध्वीश्री संवेगप्रियाजी की सेवा एवं दर्शन का लाभ लिया।

महिला मंडल ने दोडनिकुंदी स्थित गौशाला में गौमाता की सेवा की और हरा घास खिलाया। गौशाला में विराजित साध्वीश्री आगमश्रीजी के दर्शन किए। इस अवसर पर चंचलबाई आच्छा ने कहा कि महिलाएं समाज की अभिन्न और सशक्त अंग हैं। महिला प्रत्येक समाज की शोभा होती हैं और महिलाओं को विकास के सभी अवसर मिलने चाहिए। 31 महिला सदस्याओं ने शंकरपुरम के नवनिर्मित आदिनाथ मंदिर के भी दर्शन किए। इंदिराबाई गादिया एवं मंजूबाई लोढ़ा ने व्यवस्था में सहयोग दिया।

आमंत्रण

बेंगलूरु के सदगुरु सदाफल देव आदर्श गौशाला राजनकुंटे में सद्गुरु आचार्यश्री स्वतंत्र देवजी व विज्ञानदेवजी के सान्निध्य में 20 अप्रैल को आध्यात्मिक समारोह का आयोजन किया जा रहा है जिसके लिए गौशाला के हेमंतकुमार, राजेंद्र लखोटिया, नंदकिशोर दरक एवं योगेशकुमार ने गोभक्त महेंद्र मुणोत को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया तथा मुणोत को आमंत्रण पत्र भेंट किया।

ब्यावर संघ, युवा और लेडीज विंग ने किया जीतो नवकार महामंत्र दिवस का प्रचार

बेंगलूरु/ दक्षिण भारत। स्थानीय ब्यावर संघ, युवा शाखा और लेडीज विंग द्वारा बेंगलूरु में जीतो द्वारा 9 अप्रैल को आयोजित होने वाले नवकार महामंत्र दिवस के लिए प्रचार प्रसार किया। युवा अध्यक्ष ललित डाकलिया ने बताया कि विश्व शान्ति, समाज कल्याण और समाज की एकता के लिए जीतो ने नवकार महामंत्र दिवस आयोजन की शुरुआत कर अच्छी पहल की है। इस अवसर पर ब्यावर संघ के चेयरमैन अरविन्द खिंवेसरा, अध्यक्ष पदम बोहरा, महामंत्री अरविन्द कोठारी, कोषाध्यक्ष दिनेश लोढ़ा, युवा अध्यक्ष ललित डाकलिया, महामंत्री कुलदीप छाजेड़, सहमंत्री नरेश बोहरा, सहकोषाध्यक्ष भरत कोठारी, लेडीज विंग की चन्द्रकला डाकलिया, जीया हिंगड़, कंचन छाजेड़, मोनिका कुमट, संगीता पारख, सीमा बोहरा सहित अनेक सदस्य उपस्थित थे।

महावीर जन्मकल्याणक महोत्सव हेतु पंडाल निर्माण का कार्य आरंभ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। समस्त जैन समाज के सहयोग से जैन युवा संगठन द्वारा 10 अप्रैल को फ्रीडम पार्क में प्रभु महावीर का 2624वां जन्मकल्याणक महोत्सव आयोजित किया जा रहा है जिसके लिए पंडाल निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। गुरुवार को संगठन के अध्यक्ष महावीर मुणोत ने बताया कि संगठन के सभी सदस्य जन्मकल्याणक महोत्सव के विशाल आयोजन के लिए कार्यरत हैं। संस्था के मंत्री नीरज कटारिया ने बताया कि हर वर्ष की भांति जन्मकल्याणक महोत्सव भव्यता से मनाया जाएगा। पंडाल समिति के चेयरमैन आशीष कोठारी ने पंडाल संबंधित जानकारी देते हुए कहा कि फ्रीडम पार्क में भगवान महावीर के जन्मस्थान कुंडलपुर नगर की रचना हेतु भूमि पूजन से पंडाल कार्य विधिवत रूप से आरंभ हुआ। फ्रीडम पार्क में सामायिक के लिए विशेष सामायिक कक्ष, विशेष चैत्र महीने की ओली तप आराधना हेतु तपस्वियों के लिए आयंबिल कक्ष की व्यवस्था भी की जा रही है।

स्टाल कमेटी के चेयरमैन विनय गांधी ने बताया कि इस वर्ष 60 स्टालों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इस मौके पर उपाध्यक्ष मुकेश सुराणा, कोषाध्यक्ष सन्तोष डुंगरवाल सहित अनेक सदस्य उपस्थित थे।

सरकार अच्छे उद्देश्य के साथ लायी है वक्फ संशोधन विधेयक : देवेगौड़ा

बेंगलूरु/नई दिल्ली। राज्यसभा में बृहस्पतिवार को जनता दल (एस) नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि सरकार वक्फ संशोधन विधेयक एक अच्छे उद्देश्य से लेकर आयी है तथा दानदाताओं की संपत्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उच्च सदन में वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 पर चर्चा में भाग लेते हुए पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने कहा कि वह इस विधेयक को लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि दानदाताओं की संपत्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए या उसे भूमि माफिया के हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस विधेयक के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि लोगों ने जिस उद्देश्य के लिए संपत्ति दान की है, उसका उपयोग उसी मकसद के लिए किया जाए। उन्होंने कहा कि यह सोचने की बात है जिस पार्टी का चालीस साल तक अल्पसंख्यकों ने साथ दिया, आज क्यों उनका साथ छोड़ दिया?

देवेगौड़ा ने कहा कि एक समय वह भी कांग्रेस में थे। उन्होंने कहा कि जब वह मुख्यमंत्री थे उन्होंने अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए कई उपाय किए थे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने विभिन्न जातियों को आरक्षण दिया। उन्होंने पूछा कि 2014 की लोकायुक्त रिपोर्ट का क्या हुआ, उस पर कोई कार्रवाई हुई कि नहीं? पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से जो संशोधन लाये जा रहे हैं, यदि किसी को उन्हें लेकर आपत्तियां हैं तो वे अदालत में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार की भावनाओं को आहत नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह एक अच्छे उद्देश्य के साथ इस विधेयक को लेकर आयी है।

स्वागत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

बेंगलूरु के भारतीय राजपुताना सेवा संगठन द्वारा शुक्रवार से तीन दिवसीय श्रीराम कथा का आयोजन कटमनल्लूर गेट क्षेत्र के अभय अंजनी स्वामी मंदिर में दोपहर 3.30 बजे से किया जा रहा है। कथा में अयोध्या धाम की कथा वाचिका देवी राजनंदिनीजी कथा वाचन करेंगी जो कि गुरुवार को बेंगलूरु पहुंच चुकी हैं। संगठन के सदस्यों व महिला सदस्याओं ने पूरी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। संगठन के अध्यक्ष अनिलकुमार सिकरवार ने कथा की व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Aditya at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006.
Regn No. RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520 **Editor : Bhupendra Kumar** (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar.
Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.